● वर्ष : 05 ● अंक : 27
● गाजियाबाद, गुरुवार 21 मई 2026
● पृष्ठ-6 ● मूल्य : दो रूपये
● RNI No. - UPHIN/2022/84480
E-mail: swastiksaharanews@gmail.com
www.swastiksahara.com

नई दिल्ली, हरियाणा, गुरुग्राम, लखनऊ, नोएडा, मेरठ, हापुड़ और एनसीआर में सर्वाधिक प्रसारित

स्वास्तिक सहारा

गाजियाबाद से प्रकाशित
हिन्दी दैनिक

भूले नहीं कि जीवन का व्यवसाय
व्यवसाय नहीं बल्कि जीवन है।

भारत बना दुनिया का सबसे गर्म देश!

100 सबसे गर्म शहर भारत में, तपती गर्मी और लू से हर किसी का जीना मुहाल

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। पूरा देश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है और उत्तर, मध्य तथा पूर्वी भारत के अनेक हिस्सों में तापमान लगातार नए कीर्तिमान बना रहा है। मंगलवार दोपहर को भी भारत ने वैश्विक तापमान चार्ट पर अपना दबदबा बरकरार रखा। दोपहर करीब 2:30 बजे AQI.in की लाइव तापमान रैंकिंग के अनुसार, दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से सभी भारत में ही स्थित थे। यह देश भर में जारी भीषण गर्मी की लहर की तीव्रता और व्यापकता को रेखांकित करता है। रैंकिंग से पता चला कि दोपहर होते-होते तापमान में और वृद्धि हुई, यहां तक कि सूची में सबसे नीचे के शहरों में भी भीषण गर्मी दर्ज की गई, और यहां भी तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे स्पष्ट है कि गर्मी का दायरा कितना व्यापक हो चुका है।

इस सूची में केवल छोटे कस्बे ही नहीं, बल्कि देश के प्रमुख शहर भी शामिल रहे। नई दिल्ली, फरीदाबाद, चंडीगढ़, जम्मू, आगरा, अयोध्या, ग्वालियर, कोटा और रायपुर जैसे शहरों में भीषण लू का असर दिखाई दिया। दोपहर तक चंडीगढ़, जम्मू, बठिंडा, पठानकोट, बरेली, झांसी, कैथल और हरिद्वार जैसे कई शहर 46 डिग्री तापमान के दायरे में पहुंच गए थे। वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के अनेक शहरों में तापमान 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया।

पूर्वी भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है। आसनसोल और दुगार्पुर में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि धनबाद में पारा 44 डिग्री दर्ज किया गया। नई दिल्ली वैश्विक सूची में 99वें और फरीदाबाद 100वें स्थान पर रहे, जहां तापमान 44 डिग्री रहा। यह स्थिति दशार्ती है कि लू अब केवल कुछ राज्यों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के व्यापक भूभाग को अपनी चपेट में ले चुकी है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राहत की संभावना कम बताई है। विभाग के अनुसार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और विदर्भ में इस सप्ताह लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रह सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19 से 24 मई तक तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 21 मई तक गंभीर गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार की गर्मी सामान्य मौसमी चक्र से कहीं अधिक खतरनाक बनती जा रही है। बेंगलुरु स्थित तक्षशिला संस्थान के भूस्थानिक अनुसंधान कार्यक्रम के प्रमुख प्रोफेसर वाई नित्यानंदम का कहना है कि अप्रैल और मई में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अधिक गर्मी होना सामान्य बात है, क्योंकि इस समय तेज सौर विकिरण, शुष्क हवाएं और मिट्टी में नमी की कमी रहती है।

केदारनाथ मार्ग पर भूस्खलन में फंसे दस हजार से अधिक श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला

देहरादून। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भगवान शिव के ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के पैदल यात्रा मार्ग पर मंगलवार देर रात भूस्खलन में फंसे लगभग दस हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं को राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) ने सुरक्षित निकाल लिया है। एसडीआरएफ के कमांडेंट आईपीएस अर्पण यदुवंशी ने बुधवार सुबह यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोनप्रयागझगौरीकुंड के मध्य मुनकटिया क्षेत्र में अचानक भूस्खलन होने से मुख्य सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया। मार्ग बाधित होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस गए। रात्रि का समय, खराब मौसम, पहाड़ी क्षेत्र में लगातार गिरता मलबा तथा यात्रियों की भारी भीड़ के कारण स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण बनी हुई थी। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना जिला नियंत्रण केंद्र रुद्रप्रयाग द्वारा रात 21:16 बजे एसडीआरएफ को मिली। सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में सोनप्रयाग टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटनास्थल के लिए गई।

'आपका प्रधानमंत्री, आपका गृह मंत्री गद्दार है', राहुल गांधी का विवादित बयान

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को रायबरेली में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया। राहुल गांधी ने जनसभा में आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपका प्रधानमंत्री, आपका गृह मंत्री गद्दार है। कांग्रेस ने राहुल गांधी का यह वीडियो खुद सोशल मीडिया पर साझा किया है।

राहुल गांधी ने कहा कि जब भी इखढ-फ्रर के लोग आपके सामने आएं और नरेंद्र मोदी-अमित शाह की बात करें तो आप उनसे खुलकर कहिए नरेंद्र मोदी-अमित शाह गद्दार हैं। इखढ-फ्रर गद्दार हैं, क्योंकि आप लोगों ने मिलकर देश को बेचने का काम किया है। इखढ-फ्रर ने संविधान पर, वीरा पासी जी, गांधी जी और अंबेडकर जी पर हमला किया है।

'मोदी सरकार ने भारत का आर्थिक सिस्टम बेच दिया'

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। वे आपसे कहेंगे, रोएंगे और कहेंगे कि मेरी गलती नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है क्योंकि इन्होंने इसे (संविधान) खत्म किया है।

'अंबानी पेट्रोल हिंदुस्तान से बाहर भेज रहे'

पेट्रोल–डीजल के बढ़े दामों पर राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव से पहले कहा गया कि पेट्रोल, गैस की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे। आज जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो अंबानी पेट्रोल हिंदुस्तान से बाहर भेज रहे हैं। अंबानी रूस से पेट्रोल खरीदकर बाहर बेचते हैं और उस पैसे से वे नरेंद्र मोदी की फंडिंग करते हैं। यह सच्चाई है।

पाकिस्तान की भाषा बोल रहे राहुल गांधी- बीजेपी

राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी 140 करोड़ देशवासियों को गद्दार बता रहे हैं। वे टुकड़े–टुकड़े गैंग के लीडर हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिस तरह से पाकिस्तान की भाषा होती है, ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी की भाषा है। ऐसे शब्दों का प्रयोग सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी करते हैं।

ऑरेंज कैप पर वैभव सूर्यवंशी का कब्जा

जयपुर। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 की ऑरेंज कैप की दौड में मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स (आरआर) और लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के बीच खेले गये मुकाबले में पहले मिचेल मार्श और फिर वैभव सूर्यवंशी ने कब्जा किया। मिचेल मार्श एक सप्ताह पहले सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजो की सूची में आसपास भी नहीं थे आरआर के खिलाफ 57 गेंदों पर 96 रनों की पारी और इससे पहले अपनी पिछली दो पारियों में 111 और 90 रन बनाकर वह 563 रनों के साथ इस सूची में शीर्ष पर पहुंच गए। लेकिन वह शीर्ष स्थान पर अधिक देर नहीं रह पाए, क्योंकि अब नंबर वैभव सूर्यवंशी का था। वैभव सूर्यवंशी न एक बार फिर आक्रामक पारी खेली।

मायावती से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता, बसपा सुप्रीमो ने ठुकराई मुलाकात, गरमाई यूपी सियासत

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। बुधवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मायावती से मिलने का प्रयास किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख द्वारा कथित तौर पर मिलने से इनकार करने के बाद उन्हें बिना मुलाकात के ही लौटना पड़ा। कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम और सांसद तनुज पुनिया मायावती के आवास पर पहुंचे और उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। खबरों के मुताबिक, सुरक्षाकर्मियों ने बसपा प्रमुख को अपना संदेश पहुंचाया, लेकिन मायावती ने मुलाकात से इनकार कर दिया।

राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जा रही थीं कि राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे से पहले कांग्रेस नेता मायावती से कुछ राजनीतिक मामलों पर चर्चा करना चाहते थे। हालांकि, अंततः यह मुलाकात नहीं हो सकी। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए तनुज पुनिया ने कहा कि कांग्रेस कार्यालय से निकलने के बाद वह और राजेंद्र पाल गौतम मायावती के आवास पर उनका हालचाल जानने गए थे। संदर्भ स्पष्ट करते हुए पुनिया ने कहा कि कांग्रेस के एससी विभाग की एक बैठक पार्टी कार्यालय में हुई थी, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

चर्चा के दौरान मायावती के स्वास्थ्य का मुद्दा उठा, जिसके बाद नेताओं ने उनसे शिष्टाचार भेंट करने का निर्णय लिया क्योंकि उनका आवास कांग्रेस कार्यालय के निकट ही स्थित था। पुनिया ने बताया कि राजेंद्र पाल गौतम ने मायावती से मिलने का सुझाव दिया क्योंकि वे समाज की वरिष्ठ नेता हैं और उनकी उम्र 70 वर्ष के करीब है। कांग्रेस सांसद ने स्पष्ट किया कि कोई पूर्व नियुक्ति या फोन कॉल नहीं की गई थी और उन्होंने केवल अनौपचारिक रूप से पूछा था कि क्या वे व्यस्त न होने पर उनसे संक्षिप्त मुलाकात कर सकते हैं।

पुनिया ने कहा कि हमें किसी ने नहीं भेजा था, न ही इसमें कोई राजनीतिक संदेश था। चूंकि वह दलित समुदाय की एक प्रमुख नेता हैं, इसलिए हम केवल उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने गए थे।

प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट-यूजी परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ बुधवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री प्रधान ने अधिकारियों को फर्जी जानकारी, दुष्प्रचार और अफवाह फैलाने वाले चैनलों की पहचान कर उन्हें ब्लॉक और हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को शिक्षा मंत्रालय, एनटीए और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर तेजी से कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने कहा कि छात्रों को भ्रामक सूचनाओं से बचाना और परीक्षा प्रणाली में जनता का भरोसा बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम और सतर्कता बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और एनटीए के महानिदेशक ने भी हिस्सा लिया। अधिकारियों ने परीक्षा की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए संभावित कमजोरियों की पहचान और समय रहते निवारक एवं सुधारात्मक कदम उठाने पर चर्चा की।

पीडीए ऑडिट रिपोर्ट जारी कर अखिलेश का आरोप, बीजेपी सरकार कर रही आरक्षण की लूट

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को भाजपा सरकार पर आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लोगों को अदालतों का रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यादव ने आरक्षण की लूट पर पीडीए ऑडिट नामक एक दस्तावेज जारी किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पीडीए ऑडिट और आरक्षण की लूट पर यह दस्तावेज लगातार बेहतर होता रहेगा और इसमें और अधिक आंकड़े शामिल किए जाएंगे।

यादव ने जून 2023 में 'पीडीए' शब्द गढ़ा था, जिसका अर्थ है 'पिछड़े', 'दलित' और 'अल्पसंख्यक'। उन्होंने कहा कि वर्चस्ववादी ताकतें रोजगार बाजार में आरक्षण को खत्म कर रही हैं। वे 'एनएफएस' (उपयुक्त नहीं पाया गया) का भ्रामक नारा फैला रही हैं और अपने जैसी विचारधारा वाले लोगों को पिछले दरवाजे से नौकरी दिलवाने में लगी हैं। भाजपा छल कर रही है। भाजपा असमानता के खिलाफ सदियों पुरानी इस लड़ाई को अनुचित तरीकों से जीतना चाहती है। वह तीसरे पक्ष - न्यायपालिका - को भी प्रभावित करने की हद तक जा रही है। उन्हें समानता नहीं चाहिए।

सत्ताधारी भाजपा को निशाना बनाते हुए यादव ने कहा कि अगर छात्रों और उम्मीदवारों को संवैधानिक प्रावधानों को लागू करवाने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़े, तो यह समझा जाना चाहिए कि सरकार पक्षपातपूर्ण है।

उन्होंने आरोप लगाया कि अगर हमें संवैधानिक अधिकारों के लिए अदालतों का रुख करना पड़े, तो इसका मतलब है कि सरकार पक्षपातपूर्ण है। और जो पक्षपातपूर्ण होता है, वह विश्वासघाती भी होता है। पक्षपात अपने आप में अन्याय है क्योंकि यह अधिकारों को छीन लेता है।'

संसद प्रमुख ने आरक्षण को सामाजिक न्याय और समानता का साधन बताया। उन्होंने कहा कि आरक्षण सुरक्षा है। आरक्षण सामाजिक समन्वय का एक उपकरण और माध्यम भी है। भाजपा सरकार की मनमानी कार्रवाई का जिक्र करते हुए यादव ने कहा कि अगर भाजपा सरकार को बुलडोजर का इस्तेमाल करना ही है, तो उन्हें असमानता की खाई को पाटने और सभी को उनका उचित आरक्षण दिलाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए।

दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन साईबर क्लीन': 40 करोड़ के ऑनलाईन फ्रॉड का पदार्फाश, 89 अपराधी शिकंजे में

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने अप्रैल में पश्चिमी दिल्ली में एक महीने तक चले अभियान के दौरान कई अंतरराज्यीय साइबर जालसाज गिरोहों का भंडाफोड़ किया और 89 अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया गया। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली सहित कई राज्यों में चलाए गए अभियानों के दौरान 35 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, 54 लोगों को पाबंद किया गया और साइबर धोखाधड़ी के 34 मामलों को हल किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इन गिरोह में 'डिजिटल अरेस्ट', निवेश के नाम पर ठगी, एपीके फाइल के जरिए फोन हैक कर धोखाधड़ी करने, फर्जी 'डेटिंग' सदस्यता और 'म्यूल' (कमीशन पर मिलने वाले) खाते उपलब्ध कराने वाले शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान से करीब 40 करोड़ रुपये के लेनदेन में शामिल साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का पदार्फाश हुआ है। अभियान के दौरान, पुलिस ने 14.18 लाख रुपये नकद, 359 सिम कार्ड, 218 एटीएम कार्ड, 88 मोबाइल फोन, 78 चेक बुक, पांच पासबुक, तीन क्रेडिट कार्ड, दो लैपटॉप, एक पेन ड्राइव और साइबर धोखाधड़ी की गतिविधियों में कथित रूप से इस्तेमाल की गई एक कार बरामद की। पुलिस ने बताया कि टीमों ने महीने के दौरान बैंकों के साथ समन्वय करके 1.11 करोड़ रुपये ठगों के पास जाने से रोके। इसके अतिरिक्त, अदालती आदेशों के माध्यम से पीड़ितों को 51.95 लाख रुपये वापस किए गए। एक बड़े अभियान में, पुलिस ने पश्चिमी दिल्ली के करमपुरा से कथित तौर पर संचालित हो रहे एक अत्यधिक संगठित 'म्यूल' खाता और ओटीपी साझा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने डीएल ऑफिस नामक एक सोशल मीडिया ग्रुप का इस्तेमाल ओटीपी साझा करने और पूरे भारत में साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले 'म्यूल' बैंक खातों को संचालित करने के लिए किया।

आरोपियोंकी पहचान बिट्टू चौधरी, लविश चुघ, ऋषि, अरुण सिंह, आशीष और दीपक भट्ट के रूप में हुई है। उन्होंने कथित तौर पर छापेमारी के दौरान एक इमारत की चौथी मंजिल से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया।

पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला! धर्म आधारित वर्गीकरण योजनाएं बंद, 66 समुदायों को किया नियमित

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में आरक्षण व्यवस्था और जातिगत समीकरणों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार ने धर्म आधारित वर्गीकरण योजनाओं को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही, वर्ष 2010 से पहले राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग (डइउ) आरक्षण सूची में शामिल 66 समुदायों को नियमित (र्फ़ें४ं१ि) कर दिया गया है, जिससे सात फीसदी कोटे के लिए उनकी पात्रता दोबारा बहाल हो गई है।

यह कदम राज्य मंत्रिमंडल के उस निर्णय के बाद उठाया गया है, जिसके तहत मई 2024 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुपालन में राज्य की मौजूदा अन्य पिछड़ा जाति (ओबीसी) सूची को रद्द कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय के फैसले में 2010 और 2012 के बीच जोड़े गए 77 अतिरिक्त समुदायों को जारी किए गए ओबीसी दर्जे और प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया गया था। विशेषज्ञों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित जनगणना से पहले यह घटनाक्रम जातिगत समीकरणों को नया रूप दे सकता है और इसके दूरगामी सामाजिक-आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि एक ही श्रेणी में रखे गए ये समुदाय (जिनमें से तीन मुस्लिम समुदाय हैं) अब सरकारी सेवाओं में सात प्रतिशत आरक्षण के पात्र होंगे।

शहर की सुंदरता और ग्रीनरी पर विशेष कार्य करें अधिकारी नगर आयुक्त ने दिए निर्देश

मानसून से पहले वृहद प्लांटेशन की तैयारी करें उद्यानः नगर आयुक्त

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक द्वारा शहर की ग्रीनरी और सुंदरता को बढ़ाने के लिए उद्यान तथा निर्माण विभाग अधिकारियों व टीम से बैठक की गई, बैठक मुख्य अभियंता निर्माण नरेंद्र कुमार चौधरी, प्रभारी उद्यान डॉक्टर अनुज, निर्माण तथा उद्यान विभाग अवर अभियंता अधिशासी अभियंता सुपरवाइजर भी उपस्थित रहे, नगर आयुक्त द्वारा शहर की ग्रीनरी बढ़ाने शहर के सौंदर्यकरण पर विशेष कार्य करने के निर्देश टीम को दिए, मालियों की उपस्थिति को लेकर भी नगर आयुक्त द्वारा उद्यान विभाग अधिकारियों को मॉनिटरिंग बढ़ाने के लिए कहा गया।

नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि शहर को स्वच्छता के साथ-साथ सुंदर बनाना भी निगम की प्राथमिकता है जिसके क्रम में निर्माण तथा उद्यान विभाग टीम को संयुक्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

ग्रीन बेल्ट और सेंट्रल वर्ज पर लगे हुए पेड़ पौधों की कटिंग का कार्य, धूप को देखते हुए अधिक से अधिक पानी छिड़काव का कार्य, शहर में पार्कों में लगी घास और पेड़ पौधों पर पानी डालने का कार्य विशेष रूप से किया जाए निर्देश दिए गए, निर्माण विभाग

- शहर की ग्रीन बेल्ट, सेंट्रल वर्ज और पार्कों को सुसज्जित करने हेतु मालियों को दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग

द्वारा सेंट्रल वर्ज ग्रीन बेल्ट या पार्क में हो रही टूट-फूट और मरम्मत के कार्यों को करने के लिए कहा गया, प्रमुख चौराहों और स्थान पर विशेष रूप से ग्रीनरी बढ़ाने की निर्देश दिए गए।

गाजियाबाद नगर निगम मानसून से पहले ही स्थान का चयन प्लांटेशन के लिए करें नगर आयुक्त द्वारा बैठक में निर्देशित किया गया, मोहन नगर चौराहा, कवि नगर चौराहा, वसुंधरा चौराहा, इंदिरापुरम चौराहा, सिटी जोन चौराहा, विजयनगर चौराहा पर ग्रीनरी बढ़ाने के लिए भी टीम को निर्देश दिए गए।

गाजियाबाद को एक नया स्वरूप उद्यान विभाग द्वारा दिया जाए जिसमें फुलवारी, ग्रीनरी पर कार्य करने के लिए कहा गया। शहर की पहचान हरियाली बने सुपरवाइजर मालियों को विशेष ट्रेनिंग देने के लिए भी उद्यान विभाग को निर्देश दिए गए। सभी पार्कों और ग्रीन बेल्ट में नलकूप प्रत्येक दशा में चले, उद्यान विभाग की ठेकेदार मेंटेनेंस के कार्य में लापरवाही ना करें मॉनिटरिंग बढ़ाने के लिए उद्यान विभाग टीम को निर्देशित किया गया।

प्राधिकरण को 18 सम्पत्तियों की नीलामी से लगभग प्राप्त होगें रू0 155.15 करोड़

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 20.05.2026 को हिन्दी भवन, लोहिया नगर, गाजियाबाद में विभिन्न योजनाओं के रिक्त व्यवसायिक/आवासीय भूखण्डों के साथ-साथ कन्वीनियेन्ट शॉपिंग भूखण्ड, दुकान भूखण्ड, व हॉस्पिटल/ नर्सिंग होम एवं दुकान भूखण्ड इत्यादि भूखण्डों की नीलामी प्राधिकरण के द्वारा हिन्दी भवन, लोहिया नगर, गाजियाबाद में आयोजित की गई। इस नीलामी में कोयल एन्क्लेव योजना के 02 ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों की नीलामी से रू0 110.26 करोड़, कौशाम्बी योजना पॉकेट-ए0 के आवासीय भूखण्ड 01 से रू0 11.46 करोड़, वैशाली योजना सैक्टर-03 के 01 नर्सिंग होम भूखण्ड से रू0 12.88 करोड़, इन्दिरापुरम न्यायखण्ड-3 योजना के 01 कन्वीनियेन्ट शॉपिंग भूखण्ड से रू0 0.36 करोड़, इन्दिरापुरम ज्ञानखण्ड-3 योजना के दुकान भूखण्ड 06 से रू0 06.52 करोड, प्रताप विहार योजना के 01 डिस्पेन्सरी भूखण्ड से रू0 04.09 करोड़, इन्द्रप्रस्थ योजना पॉकेट-एच के व्यवसायिक भूखण्ड 04 से रू0 4.83 करोड, अम्बेडकर रोड़ डिस्ट्रिक सेन्टर योजना के व्यवसायिक भूखण्ड 01 से रू0 03.86 करोड, एवं संजय नगर सैक्टर-23 योजना के रिक्त भूमि से रू0 0.55 करोड, की नीलामी उच्चतम बोली के अनुसार सम्पन्न हुयी। इस प्रकार कुल 18 सम्पत्तियों के सापेक्ष प्राधिकरण को लगभग कुल रू0 155.15 करोड़ की सम्भावित आय प्राप्त होगी।

प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि यह नीलामी पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं नियमों के अनुरूप सम्पन्न हुई। नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग आगामी विकास परियोजनाओं, आधारभूत संरचना निर्माण तथा नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु किया जाएगा।

गाजियाबाद में 22 मई से शुरू होगा मकान सूचीकरण एवं गणना अभियान

गाजियाबाद (स्वास्तिक सहारा)। अंजनी कुमार सिंह जिला जनगणना अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) ने जानकारी देते हुए बताया कि जनगणना–2027 के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद में आगामी चरण–मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना (एच.एल.ओ) (22 मई–20 जून 2026 तक 30 दिन की अवधि में) के कार्य को गुणवतापूर्ण, समयबद्ध तथा जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशी के अनुसार पूर्ण कराने हेतु सभी चार्ज अधिकारी जनपद गाजियाबाद के साथ जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद की अध्यक्षता में आज दिनांक 19.05.2026 को महात्मा गांधी सभागार में सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी चार्ज अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि सभी प्रगणको और सुपरवाईजर को प्रगणक ब्लाक आंवटित कर नियुक्ति पत्र आज ही प्राप्त कराये। सभी प्रगणको और सुपरवाईजर अपने आंवटित क्षेत्रों मे दिनांक 21.05.2026 को भ्रमण कर क्षेत्र की पहचान कर लें तथा 22.05.2026 से 23.05.2026 के मध्य ले आउट मेप तैयार करें।

किसान दिवस में मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। विकास भवन स्थित दुर्गावती देवी सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने किसानों को सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी तथा उनकी समस्याएं सुनी गईं।

उप कृषि निदेशक राम जतन मिश्र ने बताया कि गत किसान दिवस में प्राप्त शिकायतों की अनुपालन आख्या किसानों के समक्ष प्रस्तुत की गई। कई शिकायतों के निस्तारण पर किसानों ने संतोष व्यक्त किया, जबकि लंबित मामलों में मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष बिजेन्द्र सिंह ने गन्ना भुगतान में तेजी लाने और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग उठाई। इस पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला गन्ना अधिकारी के प्रतिनिधि ने जानकारी दी कि 25 जनवरी 2026 तक का गन्ना भुगतान 20 मई को किसानों के बैंक खातों में भेज दिया जाएगा। शेष भुगतान भी जल्द जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी ने जिला गन्ना अधिकारी को शेष भुगतान की समयसीमा तय कर अवगत कराने के निर्देश दिए। ग्राम मोरटा के रास्ते में जलभराव की समस्या पर मुख्य अभियंता नगर निगम को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था कर समस्या के समाधान के निर्देश दिए गए। किसान दिवस में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी मनोज नागर, छोटे चौधरी, सतेन्द्र तोमर सहित बड़ी संख्या में किसानों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपे। कार्यक्रम में विद्युत, सिंचाई, गन्ना, लोक निर्माण और पशुपालन विभाग सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के अंत में मुख्य विकास अधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा शिकायतकताओं को कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

नेहरू वर्ल्ड स्कूल का कैम्ब्रिज आईजीसी एसई ग्रेड 10 परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। नेहरू वर्ल्ड स्कूल ने कैम्ब्रिज आईजीसी एसई ग्रेड 10 परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर शैक्षणिक उत्कृष्टता का परिचय दिया है। विद्यालय ने 100% परिणाम के साथ शानदार उपलब्धि हासिल की है। विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग ने इस सफलता को संभव बनाया। इस वर्ष विद्यालय के विद्यार्थियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय प्रदर्शन करते हुए उत्कृष्ट ग्रेड प्राप्त किए। ए - ए ग्रेडः 86% ए - सी ग्रेडः 99% पास प्रतिशतः 100% विद्यालय के प्रमुख प्रदर्शनकर्ताः भार्गवी सिन्हा व ध्रुव गर्ग ने सभी 7 विषयों में ए ग्रेड प्राप्त कर विद्यालय टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। अद्रिका सिंघल ने 6 ए और 1 ए ग्रेड प्राप्त किए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आशिता त्यागी तथा त्रिशा भाटिया ने 5 ए लाकर संयुक्त रुप से तीसरे स्थान पर कब्जा किया।

विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि यह परिणाम विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वैश्विक दृष्टिकोण और समग्र विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दशार्ता है। विद्यालय की एग्जीक्यूटिव हेड ने कहा, हमारे विद्यार्थियों ने कैम्ब्रिज आईजीसीएसई जैसे अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर यह सिद्ध किया है कि समर्पण और सही मार्गदर्शन से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

यह उपलब्धि विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है।

हमें अपने छात्रों पर गर्व है और विश्वास है कि वे भविष्य में भी नई ऊँचाइयाँ हासिल करेंगे। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन का आईजीसीएसई कार्यक्रम विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम है, जो विद्यार्थियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करता है। नेहरू वर्ल्ड स्कूल की यह उपलब्धि विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत बनाती है।

जाग उठा है देश का सोया अभिमान विषय पर गोष्ठी सम्पन्न

भारत राष्ट्रों उत्थान की और अग्रसरः आर्य रविदेव गुप्ता

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। केन्द्रीय आर्य युवक परिषद के तत्वावधान में जाग उठा है देश का सोया अभिमान विषय पर ऑनलाइन गोष्ठी का आयोजन किया गया।यह कोरोना काल से 781 वाँ वेबीनार था। वैदिक प्रवक्ता आर्य रविदेव गुप्त ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद से राष्ट्रीय स्वाभिमान जागृत हुआ है।श्रीराम मंदिर विवाद, तीन तलाक,धारा 370 और अब भोजशाला आदि असम्भव लगनेवाले मुद्दे हल हुए हैं।अब तो नक्सलवाद भी समाप्त होने को हैं' 2014 के बाद से हिन्दू स्वाभिमान जागृत हुआ है लेकिन हिंदुओं को केवल पुलिस के भरोसे नहीं रहना अपितु स्वयं को भी आत्मरक्षार्थ सक्षम बनाना है। मुख्य अतिथि ओम सपरा ने कहा कि काम तो हुए है लेकिन अभी बहुत कार्य बाकी है जैसे गौ हत्या बंदी आदि मुद्दों पर कार्य करना शेष है।अध्यक्ष राजेश मेहंदीरत्ता ने भी हुए कार्यो की सराहना की,परिषद अध्यक्ष अनिल आर्य ने कुशल संचालन करते हुए कहा कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण आर्य ने धन्यवाद ज्ञापन किया। गायिका कौशल्या अरोड़ा, जनक अरोड़ा,प्रवीना ठक्कर, कमला हंस, रविन्द्र गुप्ता,प्रतिभा खुराना,सुधीर बंसल आदि ने मधुर भजन सुनाए।

बढ़ती गर्मी को देखते हुए धूप से बचाव हेतु नगर निगम बढ़ा रहा है कदम

नगर निगम ने नवयुग मार्केट रेड लाइट पर लगाई ग्रीन नेट, राहगिरियों को मिली राहत

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश अनुसार बढ़ती गर्मी को देखते हुए गाजियाबाद नगर निगम विशेष कार्य कर रहा है जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर पानी के प्याऊ भी लगाए गए हैं, इसी क्रम में तेज धूप से बचाव के लिए रेड लाइट पर ग्रीन नेट लगाने की कार्यवाही भी चल रही है कवि नगर जोन अंतर्गत हापुर चुंगी रेड लाइट पर ग्रीन नेट से यात्रियों या राहगिरियों को राहत मिल रही है नगर आयुक्त के निर्देश अनुसार सिटी जोन नवयुग मार्केट रेड लाइट पर भी 30 मीटर लंबी ग्रीन नेट लगाई गई है जिसका स्ट्रक्चर स्थाई रूप से लगाया गया है आवश्यकता को देखते हुए ग्रीन नेट अन्य स्थानों पर लगाने की योजना भी बनाई जा रही है।

मुख्य अभियंता निर्माण नरेंद्र कुमार चौधरी द्वारा बताया गया गाजियाबाद नगर निगम निर्माण विभाग गर्मी की स्थिति को देखते हुए रेड लाइट पर धूप में खड़े रहने वाले वाहन चालकों राहगिरियों के लिए ग्रीन नेट लगाने का कार्य कर रहा है हापुर चुंगी के बाद नवयुग मार्केट रेड लाइट पर ग्रीन नेट लगाई गई है जिससे राहगीर छांव में रुक कर ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर सकेंगे, ठाकुरद्वारा जाने वाले मार्ग तथा ठाकुरद्वारा से आने वाले मार्ग दोनों तरफ नवयुग मार्केट रेड लाइट पर ग्रीन नेट लगाए गया है।

नवयुग मार्केट रेड लाइट से अधिक ट्रैफिक हापुर मेरठ दिल्ली के लिए निकलता है आवश्यकता को देखते हुए ग्रीन नेट लगाने का कार्य प्रारंभ कराया गया इसी क्रम में नगर आयुक्त द्वारा निरीक्षण करते हुए कार्य तेजी करने के निर्देश दिए तत्काल प्रभाव से कार्य पूर्ण कराया गया, ग्रीन नेट लगने से ट्रैफिक सिगनलों का पालन भी सरलता से हो रहा है छांव में रुकते हुए वाहन चालक ट्रैफिक सिग्नल का पालन कर रहे हैं।

जनगणना-2027 के प्रथम चरण को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने के निर्देश

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। जनगणना-2027 के अंतर्गत आगामी चरण मकान सूचीकरण एवं मकान गणना (एच.एल.ओ.) कार्य को निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट स्थित कक्ष संख्या-307 में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला जनगणना अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) अंजनी कुमार सिंह ने की। बैठक में जनगणना-2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकान गणना कार्य, जो 22 मई से 20 जून 2026 तक संचालित होगा, की तैयारियों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कार्य जनगणना निदेशालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराया जाए।

अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि जनगणना कार्य को कुशलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए जिला पंचायती राज अधिकारी जाहिद हुसैन तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश यादव को अपर जिला जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है। दोनों अधिकारियों को विभिन्न निकाय क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपते हुए प्रगणकों और सुपरवाइजरों के कार्यों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए।

जिला पंचायती राज अधिकारी को नगर पालिका परिषद मोदीनगर, मुरादनगर तथा नगर पंचायत डासना, पतला, निवाड़ी और फरीदनगर का चार्ज दिया गया है। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी को नगर पालिका परिषद लोनी और खोड़ा क्षेत्र का दायित्व सौंपा गया है। बैठक में निर्देश दिए गए कि संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में नियुक्त प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों से समन्वय स्थापित कर उन्हें एच.एल.ओ. एप पर लॉगिन तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया सुनिश्चित कराएं। साथ ही प्रतिदिन कार्य की समीक्षा करते हुए तय समयसीमा में कार्य पूर्ण कराया जाए।

बैठक में जिला पंचायती राज विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग तथा सूचना विभाग के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

हीट वेव और संचारी रोगों से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान आयोजित

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। जनपद में हीट वेव एवं संचारी रोगों से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कन्या वैदिक इंटर कॉलेज में विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को गर्मी के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों तथा संचारी रोगों से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई।

इस अवसर पर जिला मलेरिया अधिकारी जी.के. मिश्रा ने कहा कि अत्यधिक गर्मी के दौरान पर्याप्त पानी पीना, धूप से बचाव करना तथा साफ-सफाई बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए आसपास जलभराव न होने देने और मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. रितु वर्मा ने छात्राओं को हीट वेव के लक्षण एवं प्राथमिक उपचार की जानकारी दी। वहीं प्रधानाचार्य महिमा कटियार ने छात्राओं से स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में सहायक मलेरिया अधिकारी नरेन्द्र कुमार, विद्यालय की अध्यापिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।

सोने के आयात पर सरकार की रणनीति को व्यापारियों का समर्थन, छोटे सराफा कारोबारियों के लिए राहत की मांग

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। देश की आर्थिक मजबूती, विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा और रुपए की स्थिरता को लेकर सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियों को अब व्यापारी वर्ग का खुला समर्थन मिलने लगा है। इसी क्रम में विकास भवन गौतमबुद्ध नगर में राज्य कर विभाग की ओर से जनपद के व्यापार मंडलों, सराफा एवं बुलियन कारोबारियों के साथ एक महत्वपूर्ण संवाद बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य कर विभाग के अपर आयुक्त (कमिश्नर) संदीप भागिया ने की। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ व्यापार जगत से जुड़े प्रमुख प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सोने के आयात, विदेशी मुद्रा पर उसके प्रभाव तथा घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए कमिश्नर संदीप भागिया ने सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार व्यापारियों को सोने का कारोबार बंद करने के लिए नहीं कह रही है। सरकार केवल यह चाहती है कि नए सोने के आयात को सीमित कर पुराने और घरेलू सोने के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए।उन्होंने कहा कि अत्यधिक सोना आयात होने से देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है, जिससे रुपए की स्थिति प्रभावित होती है। यदि घरेलू स्तर पर उपलब्ध सोने को ही अधिक रोटेशन में लाया जाए, तो भारत आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बनेगा और वैश्विक आर्थिक दबावों का सामना बेहतर तरीके से कर सकेगा।उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष विकास जैन ने बैठक में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सरकार की नीति का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देश का व्यापारी वर्ग हमेशा राष्ट्रहित में सरकार और प्रशासन के साथ खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा देश और प्रदेश के हित में किए गए आह्वान का व्यापारी समाज पूर्ण समर्थन करता है।

विकास जैन ने कहा कि यदि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रुपए को स्थिर रखने के लिए सरकार किसी नीति को लागू करती है, तो व्यापारी वर्ग उसके पालन के लिए पूरी तरह तैयार है।यशिका डायमंड के एमडी विनय गर्ग ने भी सरकार की नीति का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा और आर्थिक मजबूती व्यापार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। व्यापारियों का कहना था कि छोटे सराफा व्यवसायियों का पूरा रोजगार सोने-चांदी के आभूषणों की दैनिक खरीद-बिक्री पर निर्भर है। ऐसे में यदि आयात नियंत्रण संबंधी नीतियां लागू की जाती हैं, तो सरकार को छोटे कारोबारियों के लिए विशेष राहत या रियायत का प्रावधान भी करना चाहिए, ताकि उनकी आजीविका प्रभावित न हो। बैठक में उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष विकास जैन, यशिका डायमंड के एमडी विनय गर्ग, एआईजीजेए के जिला अध्यक्ष योगेश वर्मा, ज्वेलरी एसोसिएशन ग्रेटर नोएडा के वाइस प्रेसिडेंट दीपक वर्मा, आरसी ज्वैलर्स के विजय सैनी, कल्याण ज्वैलर्स के प्रतिनिधि, मोहित गर्ग तथा ब्लू स्टोन की रुपाली कौशिक सहित जनपद के कई प्रमुख सराफा एवं बुलियन कारोबारी मौजूद रहे।

भारत विकास परिषद द्वारा वृंदावन में श्री बांके बिहारी के दिव्य दर्शन एवं भजन संध्या का हुआ आयोजन

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। भारत विकास परिषद नोएडा द्वारा वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के श्रीचरणों में छप्पन भोग अर्पण, दिव्य दर्शन एवं भजन संध्या का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में परिषद परिवार के सदस्य, मातृशक्ति एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री बांके बिहारी जी के दिव्य दर्शन एवं श्री आशीष गोस्वामी द्वारा पूजन-अर्चना के साथ हुआ। इसके पश्चात ठाकुर जी को श्रद्धा एवं भक्ति भाव से छप्पन भोग अर्पित किया गया। संपूर्ण मंदिर परिसर ह्लराधे-राधेह्व एवं भक्ति रस से सराबोर रहा। सायंकाल आयोजित भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक विनोद रसिक एवं उनकी टीम द्वारा प्रस्तुत मनमोहक भजनों ने सभी श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया। श्रद्धालु देर रात तक भक्ति रस में डूबे रहे तथा वृंदावन धाम की दिव्यता का आनंद लिया। इस अवसर पर परिषद के अध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता, सचिव अखिलेश भदौरिया, कोषाध्यक्ष अक्षय पारीक, महिला सहभागिता सुनीता मित्तल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यनारायण गोयल आदि उपस्थित रहे। वही कार्यक्रम के सफल आयोजन में मुख्य अतिथि सरयू प्रसाद यादव एवं परिषद के महेश बाबू गुप्ता, राजीव अजमानी शाखा सरंक्षक मधुसूदन दादू, प्रताप मेहता , राकेश कत्याल, विपिन मल्हन, नरेश शर्मा, धर्मवीर शर्मा, देवेंद्र गंगल, केशव गंगल, कुलदीप गुप्ता, रामरतन शर्मा, डी के मित्तल, राकेश गुप्ता , सौरभ गोविल कार्यक्रम संयोजक एन के अग्रवाल, अजय अग्रवाल, श्री जी गौ सदन के अध्यक्ष विकास अग्रवाल एवं सभी पदाधिकारी, सदस्य एवं सहयोगियों का विशेष योगदान रहा।

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जिला गौतमबुद्ध नगर के जेवर मंडल द्वारा किया गया व्यापारी सम्मेलन

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

गौतमबुद्धनगर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल गौतम बुध नगर की जेवर मंडल इकाई द्वारा 'व्यापारी एवं कारोबारी सम्मेलन' कार्यक्रम का शुभारम्भ एनसीआर चेयरमैन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल डॉ पीयूष द्विवेदी द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। यह आयोजन जिला अध्यक्ष संजय जैन की अध्यक्षता में हुआ। उपरोक्त कार्यक्रम में व्यापारियों एवं उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य रूप से गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेघा रूपम, ग्रेटर नोएडा डीसीपी डॉ प्रवीण रंजन सिंह एवं एसडीएम दुर्गेश सिंह द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यापारियों एवं उद्यमियों की समस्याओं को सुना गया एवं विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार मंथन कर कुछ समस्याओं का समाधान तुरत प्रभाव से किया गया तथा बाकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया। इसी क्रम में जिलाधिकारी मेघा रूपम एवं ग्रेटर नोएडा डीसीपी को व्यापार मंडल द्वारा समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौपा गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जिला गौतम बुद्ध नगर से जिला महासचिव अमित अग्रवाल, कोषाध्यक्ष नरेश बंसल, महासचिव राहुल भाटिया, सचिव सुनील वर्मा, डॉ जे एस बेदी, तनवीर, व्यापार मंडल जेवर मंडल से अध्यक्ष संजय महेश्वरी, महासचिव कुलदीप पंडित, संरक्षक जैनेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष अनिल गोयल, अंबर सिंगल समेत तकरीबन 200 से ज्यादा व्यापारियों एवं उद्यमियों ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो प्रशासन के समक्ष जेवर के व्यापारियों एवं उद्यमियों की समस्याओं से अवगत कराया गया।

शाहबेरी उपकेंद्र शुरू, 8 हजार उपभोक्ताओं मिली राहत

नोएडा। शाहबेरी क्षेत्र के हजारों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से प्रतीक्षित शाहबेरी विद्युत उपकेंद्र से बुधवार को बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई। उपकेंद्र शुरू होने से क्षेत्र के करीब 8 हजार उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा और गर्मी के मौसम में अब उन्हें अधिक सुचारू एवं बेहतर विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी। अब तक शाहबेरी क्षेत्र की बिजली आपूर्ति गाजियाबाद स्थित सुदामापुरी उपकेंद्र से संचालित की जा रही थी, जिसके चलते अधिक लोड की समस्या बनी रहती थी। कई बार ओवरलोडिंग के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित होती थी और उपभोक्ताओं को कटौती व लो-वोल्टेज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। बिजली विभाग ने बुधवार को शाहबेरी उपकेंद्र को पूरी तरह चालू कर क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं को नए उपकेंद्र से जोड़ दिया।

एडीएम न्यायिक की अध्यक्षता में गौ आश्रय स्थलों की हुई समीक्षा बैठक

गर्मी के दृष्टिगत गौशालाओं में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

गौतम बुद्ध नगर। अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) प्रियंका की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में गौ आश्रय स्थलों के संचालन, प्रबंधन एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना निदेशक नेहा सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण कुमार, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों, खंड विकास अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में गो संवर्धन एवं संरक्षण कोष में धनराशि एकत्रित करने तथा उसके प्रभावी उपयोग पर विस्तृत चर्चा की गई। एडीएम न्यायिक ने कहा कि विभिन्न संस्थानों, सामाजिक संगठनों एवं जनसहभागिता के माध्यम से इस कोष को सशक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने जनपदवासियों से गौ संरक्षण हेतु अधिक से अधिक सहयोग एवं सहभागिता की अपील की।

अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने निर्देश दिए कि जनपद में निराश्रित गोवंशों के शत-प्रतिशत संरक्षण के उद्देश्य से विशेष अभियान संचालित किया जाए। साथ ही सभी गौ आश्रय स्थलों में गोवंशों के लिए पर्याप्त मात्रा में भूसा, हरा चारा, स्वच्छ पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। गर्मी के मौसम को देखते हुए उन्होंने विशेष रूप से निर्देशित किया कि गौशालाओं में पर्याप्त छायादार स्थान, स्वच्छ एवं ठंडे पेयजल की व्यवस्था, पंखे एवं कूलिंग सिस्टम तथा हीट वेव से बचाव के सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जाएं, ताकि गोवंशों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त एडीएम न्यायिक ने ग्राम सभाओं की खाली पड़ी भूमि पर हरा चारा उगाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए, जिससे गौशालाओं के लिए स्थायी रूप से चारे की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि सभी नोडल अधिकारी नियमित रूप से गौशालाओं का निरीक्षण करें तथा गोवंशों की वास्तविक संख्या का सत्यापन रजिस्टर एवं पोर्टल से मिलान कर सुनिश्चित करें। साथ ही गौ आश्रय केंद्रों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों का आईपी एड्रेस एवं आईडी-पासवर्ड तीन दिवस के भीतर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने कहा कि गौ संरक्षण शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है तथा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ एक और मुकदमा

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा जाट व गुर्जर समाज की पारिवारिक व्यवस्था को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों समाज के लोग अब सड़क पर उतर कर विरोध कर रहे है। ताजा मामला मुजफ्फरनगर के सिविल लाइंस थाने का हैं जहाँ जाट महासभा के जिला अध्यक्ष की तहरीर पर भाटी के विरुद्ध समाज की भावना भड़काने व अपमानित करने का मुकदमा दर्ज किया गया है और मांग की गयी हैं कि इस मामले में कड़ी कारवाई की जाये। इस दौरान जाट महासभा के जिला अध्यक्ष धर्मवीर बालियान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती तो समाज अपने तरीके से जवाब देना जानता है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब राजकुमार भाटी पर किसी समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा हो। इससे पहले भी वे अन्य समाजों पर बयानबाजी कर चुके हैं। बता दे कि कुछ दिन पूर्व दिल्ली स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब में किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान राजकुमार भाटी ने महिलाओं को लेकर कथित विवादित टिप्पणी की थी। उनके बयान के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक संगठनों में नाराजगी बढ़ गयी हैं।

चौपाल में समस्या रखने के बाद भी समाधान नहीं होता: अशोक चौहान

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। आज गांव नंगली वाजिदपुर सैक्टर 130 में नोएडा प्राधिकरण के द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। नोएडा प्राधिकरण द्वारा आयोजित चौपाल में लोगों ने सिविल विभाग, जल एवं सीवर विभाग, विद्युत विभाग, और जन स्वास्थ्य विभाग आदि से जुड़ी समस्याएं उठाई लेकिन समाधान को लेकर अधिकारियों की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इस अवसर पर ग्राम विकास संगठन नोएडा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अशोक चौहान ने बताया कि गांव नंगली वाजिदपुर में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह खराब है। नालियों का ढलान सही नहीं होने से बरसात के समय में जल भराव की समस्या रहती है। गांव की आंतरिक सड़कों पर रेडी पटरी ओर अवैध रूप से गाड़ियां खड़ी करके अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के कारण लोगों को भारी समस्या होती है। उन्होंने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर फुट ओवर ब्रिज, गांव को सिटी बस सेवा से जोड़ने, स्वास्थ्य केंद्र, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर सेक्टर 135 के सामने से चढ़ने के लिए सड़क बनाने और जाम की समस्या के समाधान की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि गांव नंगली वाजिदपुर में सीवर लाइन ओवरफ्लो हो रही है और पानी की सप्लाई भी पर्याप्त नहीं है। गंगाजल आपूर्ति शुरू करने और पाइपलाइन पर वॉल लगाकर दुरुस्त करने की आवश्यकता है। गांव नंगली वाजिदपुर में कूड़ा उठाने की गाड़ी प्रत्येक दिन नहीं आती है। पार्क की स्थिति बेहद खराब है बच्चों के खेलने के लिए सुविधा नहीं है। कई जगह बिजली के खंबे और तार जर्जर हो चुके हैं आए दिन बिजली के तारों में आग लग जाती है। जर्जर तार हादसों को न्योता दे रहे है जिन्हें तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। मौके पर निवासियों ने कहा कि गांव में खेल का मैदान नहीं है साथी ही आवारा पशु, कुत्ते और बंदरों की बढ़ती संख्या से लोगों को परेशानी हो रही है। इन्हें तत्काल पकड़ा जाए। निवासियों ने गांव नंगली वाजिदपुर को सिटी बस सेवा से जोड़ने और डूब क्षेत्र में बनी नोएडा प्राधिकरण की अस्थाई गौशाला को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की।

ग्राम विकास संगठन नोएडा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अशोक चौहान ने कहा कि 3 वर्ष पहले भी इन समस्याओं को उठाया गया था लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। चौपाल में नहीं पहुंचे सभी विभाग के अधिकारी जिसके कारण ग्राम वासियों को स्पष्ट जवाब नहीं मिला और लोगों में नाराजगी है। इस अवसर पर नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक अनिल कुमार, डीडी.अंकित सेंगर, एपी अंकित राजपूत, सुभाष, लेखपाल मनोज सिंघल, जेई संतोष पांडेय, ग्रामीण ऋषभ चौहान, मोनू चौहान, सत्येंद्र गुर्जर, मुक्ती चौहान, आदि उपस्थिति रहे।

से. 35 मे सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। सेक्टर 35 मे सुरक्षा व्यवस्था के लिए आरडब्लूए द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता डीडी आरडब्ल्यू अध्यक्ष ठाकुर एन पी सिंह द्वारा की गई। बैठक के दौरान सेक्टर 35 की सुरक्षा व्यवस्था, मेड और ड्राइवर इत्यादि का सत्यापन, ट्रैफिक की समस्या, सेक्टर के बाहर खड़े होने वाली अनॉथराइज्ड बसे, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के उपाय इत्यादि पर चर्चा करी गई। मीटिंग में डीडी आरडब्लूए अध्यक्ष एन पी सिंह, सेक्टर 35 आरडब्लूए अध्यक्ष महिपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी राजीव चौधरी, राजीव जैन और सेक्टर 35 के निवासी मौजूद रहे। वही पुलिस विभाग से एसीपी- 2 नोएडा अनिल कुमार पांडेय, थाना अध्यक्ष सैक्टर 24 सुबोध सिंह एवं पुलिस टीम मौजूद रही।

पैतृक भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर भाकियू बलराज ने उठाई आवाज, एसडीएम दादरी को सौंपा ज्ञापन

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

दादरी। कस्बा खारी कुआं निवासी गोपाल गर्ग एवं मनोज जिंदल की पैतृक भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे एवं निर्माण कार्य के विरोध में आज भारतीय किसान यूनियन (बलराज) के पदाधिकारियों एवं कार्यकताओं ने उपजिलाधिकारी दादरी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच एवं न्याय की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि खसरा संख्या 370, नया खसरा संख्या 1161, रकबा 1265 वर्गमीटर भूमि में स्व0 शिवचरण दास एवं स्व0 प्रेमचंद की 1/3 हिस्सेदारी है। आरोप है कि सहखातेदार राकेश गोयल, राज गोयल, करण गोयल एवं जीतू गोयल द्वारा तहसील प्रशासन से सांठगांठ कर लगभग 650 वर्गमीटर भूमि का विक्रय कर दिया गया तथा लगभग 420 वर्गमीटर भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया। जबकि विपक्षीगण का उक्त भूमि में लगभग 105 वर्गमीटर का ही हिस्सा है। भारतीय किसान यूनियन (बलराज) ने आरोप लगाया कि अब शेष लगभग 200 वर्गमीटर भूमि पर भी जबरन कब्जा एवं निर्माण कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित परिवार लगातार प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि कुछ तहसील के अधिकारियों एवं स्थानीय भाजपा नेताओं के संरक्षण के कारण दबंगों के हौसले बढ़े हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन (बलराज) ने प्रशासन से मांग की है कि अवैध कब्जा एवं निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रोका जाए, निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए तथा दोषी व्यक्तियों एवं संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए। साथ ही पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र उचित कार्यवाही नहीं हुई तो भारतीय किसान यूनियन (बलराज) आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। इस अवसर पर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा रेखा सिवाल, कोषाध्यक्ष रोहित भाटी, प्रवक्ता एंव महासचिव विपिन खारी, प्रदेश महासचिव कर्मवीर खारी, महामन्त्री ब्रह्मचंद्र बैरागी, उपाध्यक्ष सोनू खारी प्रदेश, महासचिव संदीप नागर, सचिव सोरव भाटी, लालू यादव, उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी अमरीश भाटी, जिला उपाध्यक्ष कपिल शर्मा, उपाध्यक्ष इरशाद राणा, मनवर अली, खुर्शीद प्रधान, वेद प्रकाश, अजय आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

जेपी के फ्लैट खरीदार ओसी मांगने नोएडा प्राधिकरण पहुंचे

नोएडा। प्राधिकरण में बुधवार को जेपी कॉसमॉस सेक्टर-134 और केंसिंग्टन बुलेवर्ड सेक्टर-131 के फ्लैट खरीदार अधिभोग प्रमाणपत्र (ओसी) मांगने के लिए पहुंचे। फ्लैट खरीदारों ने कहा कि जेपी की परियोजनाओं को देख रही एजेंसी सुरक्षा की तरफ से जुलाई और दिसंबर-2025 में दोनों ही परियोजनाओं में ओसी के लिए आवेदन किया गया था। लेकिन अब तक आवेदन का निस्तारण नोएडा प्राधिकरण में नहीं हुआ। इसलिए फ्लैट में कब्जा नहीं मिल पा रहा है। कॉसमॉस होमबायर्स के प्रतिनिधि प्राणेश सिन्हा ने यह पक्ष एसीईओ सतीश पाल के सामने रखा। एसीईओ ने फ्लैट खरीदारों की समस्याएं सुनीं और प्राधिकरण स्तर पर प्रक्रिया की जानकारी ली। एसीईओ ने बताया कि ओसी के लिए आवेदन बिल्डर की तरफ से किया गया था। कुछ आपत्तियां थीं जो बिल्डर को वापस भिजवाई गई थीं।

बिजली की समस्याओं के लिये मुख्य अभियंता से मिले किसान

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। भारतीय किसान यूनियन (लोकशक्ति) की बैठक जिला अध्यक्ष युवा अमित गौड़ के नेतृत्व में सेक्टर 16 स्थित विद्युत विभाग कार्यालय में हुई। जिसकी अध्यक्षता भाकियू लोकशक्ति के परिवहन मंत्री ओमप्रकाश गुर्जर ने की। इस बैठक में गौतमबुद्ध नगर के हर गांव व नगर में आ रही बिजली की मुख्य समस्याओं को रखा गया। जिसमें राष्ट्रीय महासचिव चौधरी बीसी प्रधान ने विद्युत विभाग को चेतावनी देते हुए इन समस्याओं पर जल्द से जल्द संज्ञान लेते हुए समाधान करने की माँग उठायी। आगे कहा कि क्षेत्र की जर्जर हुयी पुरानी लाइन व आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए लोगों के घरों के ऊपर से जा रही लाइनें को जल्द से जल्द हटाया जाये व बढ़े हुए बिलों के लिए इधर-उधर जो चक्कर लगाए जाते हैं उनको सिर्फ एक ही जगह से समाधान किया जाय। इसके लिए ज्ञापन भी सौपा गया जिसमें लगभग 9 समस्या दी गई। सभी समस्याओं के निराकरण करने का आश्वासन मुख्य अभियंता ने दिया है। बैठक में मुख्य रुप चौधरी बीसी प्रधान, चौधरी ओमप्रकाश गुर्जर, ठाकुर अमित गौड़, सतपाल यादव, प्रताप नागर , जीता ठाकुर, ठाकुर सुनील भाटी, चौधरी महेश तंवर, ठाकुर प्रदीप भाटी, ठाकुर संजय भाटी, ठाकुर खेमे सिंह, ठाकुर शीलू सिंह, राजकुमार उर्फ मोनू, अजब सिंह भाटी, हरि अवाना, विजयपाल भाटी, हरेन्द्र बैसोया, आनंद भाटी, अरूण गौतम, अंकुर कश्यप इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सम्पादकीय

रुपए की गिरावट

भारतीय मुद्रा रुपया लगातार दबाव में है और डॉलर के मुकाबले इसका मूल्य लगभग 96 रुपये के आसपास पहुंचना गंभीर चिंता का विषय बन गया है। यह केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि देश की व्यापक आर्थिक स्थिति का संकेत भी है। रुपये का कमजोर होना सीधे तौर पर आयात, महंगाई, निवेश और आम जनता की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालता है। किसी भी देश की मुद्रा की मजबूती उस देश की आर्थिक स्थिरता, उत्पादन क्षमता और वैश्विक भरोसे का प्रतीक होती है। जब मुद्रा लगातार कमजोर होती है तो यह संकेत देता है कि अर्थव्यवस्था के भीतर कुछ संरचनात्मक समस्याएं मौजूद हैं। भारत के मामले में भी रुपये की गिरावट के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। बढ़ता आयात, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और विदेशी निवेश में कमी जैसे कारक इसमें प्रमुख हैं। भारत ऊर्जा के क्षेत्र में अभी भी काफी हद तक आयात पर निर्भर है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर देश को अधिक डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है और रुपया कमजोर होता है। इसके अलावा जब वैश्विक निवेशक अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित मानते हैं तो वे अपना निवेश अमेरिका की ओर स्थानांतरित कर देते हैं। इससे भी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं पर दबाव बढ़ता है। रुपए की गिरावट का सबसे बड़ा असर आम जनता पर महंगाई के रूप में पड़ता है। जब रुपया कमजोर होता है तो आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कई अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसका सीधा असर परिवहन लागत और उत्पादन लागत पर पड़ता है, जिससे बाजार में वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। अंततः इसका बोझ आम उपभोक्ता को उठाना पड़ता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि कमजोर रुपया निर्यात को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है, क्योंकि भारतीय वस्तुएं वैश्विक बाजार में अपेक्षाकृत सस्ती हो जाती हैं। लेकिन यह लाभ तभी संभव है जब देश का निर्यात ढांचा मजबूत हो और उत्पादन क्षमता पर्याप्त हो। यदि उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सीमित है तो केवल मुद्रा के कमजोर होने से निर्यात में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाती। ऐसे समय में सरकार और नीति-निमार्ताओं के सामने बड़ी चुनौती यह है कि वे आर्थिक संतुलन बनाए रखें। विदेशी निवेश को आकर्षित करना, निर्यात को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू उत्पादन को मजबूत बनाना जरूरी है। इसके साथ ही वित्तीय अनुशासन, स्थिर नीतियां और निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

दैनिक राशिफल

मेष: चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ।

निवेश के सुखद परिणाम आएंगे। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। किसी बड़ी बाधा के दूर होने से प्रसन्नता रहेगी।

वृषभ: इ, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो।

कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। व्यवसाय ठीक चलेगा। आय बनी रहेगी। व्यस्तता रहेगी। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे।

मिथुन: का, की, कु, घ, ङ:, छ, के, को, हा।

व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। भाग्य का साथ रहेगा।

कर्क: ही, हे, हु, हो, डा, डी, डू, डे, डो।

कारोबार में वृद्धि होगी। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। नए व्यापारिक अनुबंध होंगे। धनार्जन होगा।

सिंह: मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे।

कोर्ट व कचहरी के कार्य अनुकूल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। परिवार के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा।

कन्या: टो, पा, पी, पू, ष, ण:, ठ, पे, पो।

धनलाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आय में निश्चितता होगी। ऐश्वर्य पर व्यय होगा।

तुला: रा, री, रु, रे, रो, ता, ती, तू, ते।

जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा। सुख के साधन जुटेंगे। कारोबार में वृद्धि होगी। निवेशादि शुभ रहेंगे।

वृश्चिक: तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, यी, यू।

आय में वृद्धि होगी। भूमि व भवन संबंधी योजना बनेगी। कोई बड़ा लाभ हो सकता है। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे।

धनु: तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, यी, यू।

भागदौड़ रहेगी। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा।

मकर: भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी।

आज लेन-देन में विशेष सावधानी रखें। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। दु:खद समाचार मिल सकता है।

कुंभ: गू, गे, गो, सो, सी, सू, स, से, दा।

पराक्रम बढ़ेगा। आय में वृद्धि होगी। पराक्रम बढ़ेगा। किसी बड़े काम को करने में रुझान रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी।

मीन: दी, दू, थ, झ, यं, दे, दो, चा, ची।

आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। विवेक से कार्य करें। विरोधी सक्रिय रहेंगे। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ समाचार प्राप्त होंगे।

फिर कैसे मिले सुर मेरा-तुम्हारा

उमेश चतुर्वेदी

विधानसभा चुनावों में बड़े विपक्षी चेहरों की बड़ी नाकामी से विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। बंगाल की शेरनी कही जाने वाली ममता बनर्जी की हार ने विपक्षी खेमे के उन दलों के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई हैं, जो इन चुनावों से बेपरवाह थे। केरल की गठबंधन सरकार में वापसी की वजह से कांग्रेस थोड़ी राहत में भले ही हो, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रीय दलों को अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आने लगा है। तमिलनाडु में सत्ता की चाहत में विपक्षी गठबंधन टूट भी चुका है। कांग्रेस के हाथ ने डीएमके का बरसों पुराना साथ छोड़ नवेली टीवीके का दामन थाम लिया है। दूसरी तरफ धांधली का आरोप लगाने के साथ ही ममता बनर्जी को विपक्षी एकता, खासकर इंडिया ब्लॉक की याद आने लगी है। अब उन्हें विपक्षी एकता मजबूत करने की याद भी आने लगी हैं।

दिलचस्प यह है कि अतीत में इंडिया ब्लॉक की एकता से बेपरवाह रहीं ममता को अब उसी की बहुत याद आने लगी है। वैसे विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की ओर से भी कम गलतियां नहीं हुई हैं। राहुल गांधी का पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त के लिए ममता को खुलेआम जिम्मेदार ठहराना एक तरह से तृणमूल की ताबूत का कील ही साबित हुआ। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि विपक्षी एकता का विचार सिरे से परवान चढ़ सकता है? अतीत में एकता को लेकर जिस तरह विपक्षी खेमे में एक-दूसरे को शह और मात देने का खेल चला है, उससे क्या मुकम्मल एकता की उम्मीद बचती है? 2024 के आम चुनावों के पहले विपक्षी राजनीति को एक मंच पर लाने और भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिश तो हुई, लेकिन आपसी टकराव और वर्चस्व के चलते यह हकीकत नहीं बन पाया। 23 जून 2023 को पटना में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुआई में विपक्षी क्षत्रपों की बैठक में इंडिया ब्लॉक बनाने का फैसला तो हुआ,लेकिन नेतृत्व के मुद्दे पर एक राय नहीं बन पाई। नीतीश कुमार ने खुलकर भले ही कभी नहीं कहा, लेकिन उनकी चाहत थी कि विपक्षी गठबंधन का संयोजक उन्हें बनाया जाय। लेकिन कांग्रेसी आलाकमान की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। दरअसल कांग्रेस विपक्षी राजनीति की लगाम खुद के हाथ में ही रखना चाहती है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और एमके स्टालिन का साथ तो उसे चाहिए, लेकिन इनमें से किसी का भी नेतृत्व उसे गवारा नहीं। अपने पहले परिवार की पूरी स्वीकार्यता भले ही ना हो, लेकिन अगुआई कांग्रेस को ही चाहिए। यही वजह है कि विपक्षी राजनीति के सबसे ज्यादा स्वीकार्य चेहरा रहे नीतीश कुमार ने निराशा में उसी मोदी का हाथ थाम लिया, जिनसे वे दूर हो चुके थे।

इसके बाद का इतिहास सबको पता है।

ममता को राजनीति में पहला बड़ा ब्रेक बेशक राजीव गांधी ने दिया, लेकिन वाममोर्चा के साथ राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेसी सहयोग ने उन्हें बाद के दिनों में गांधी-नेहरू परिवार से दूर कर दिया। हालिया हार के बावजूद अपनी संघर्षशीलता के चलते ममता विपक्षी राजनीति का अब भी बड़ा चेहरा हैं। उनकी अपनी छवि अक्सर राहुल गांधी पर भी भारी पड़ती है। इंडिया ब्लॉक के विचार के वक्त पूर्व कांग्रेसी होने के नाते ममता को पता था कि कांग्रेस अपने हाथ में नेतृत्व बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, इसीलिए उन्होंने ही नीतीश कुमार और लालू यादव को पहली बैठक पटना में कराने का सुझाव दिया था। बाद के दिनों में कांग्रेस ने जैसी चाल चली, उससे विपक्षी एकता का राग बेसुरा हो गया। जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव नतीजों में दिखा भी। विपक्ष को उसी वक्त चेतना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असर यह हुआ कि हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली। बाकी कसर बीते विधानसभा चुनावों ने पूरी कर दी है।

गौर करने की बात है कि जब भी सत्ता पक्ष के उफान में विपक्ष बह जाता है, उसकी एकता की छटपटाहट बढ़ जाती है। ज्यादातर यह अस्तित्व संकट टालने का यह फौरी उपाय होता है। तब वह हार के बाद वोटों के गुणा-गणित में जुट जाता है। फिर उसे इलहाम होता है कि अगर वह एक रहता तो वह भारी पड़ता। 1962 के आम चुनावों में नेहरू को फूलपुर की सीट पर सीधी चुनौती में हार मिलने के बाद लोहिया को भी कुछ ऐसा ही लगा। तब भारी उत्सुकता और उत्साह के बावजूद लोहिया हार गए थे। इसके बाद उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का विचार दिया। तब कांग्रेस को 44 प्रतिशत से कुछ ज्यादा वोट मिले थे। लोहिया को लगा कि विरोध में पड़े 56 प्रतिशत वोटों को अगर एक किया जाता तो नतीजे कुछ और होते। गैर कांग्रेसवाद के बैनर के तले उन्होंने 1963 के उपचुनावों और 1967 के आम चुनावों में इसे आजमाया। इसका असर यह हुआ कि आठ राज्यों से कांग्रेस की विदाई हो गई। तब से सत्ता में आने वाली पार्टी के खिलाफ बाकी विपक्ष की एकता के सुर उठने की परंपरा बन गई है। कभी यह कांग्रेस के खिलाफ होता था, जिसमें वाममोर्चा और जनसंघ- बीजेपी भी शामिल रहते थे, अब यह भाजपा के खिलाफ हो रहा है।

प. बगाल के बीते विधानसभा चुनाव में ममता को जहां करीब 42 प्रतिशत वोट मिला है, वहीं बीजेपी को करीब 46 प्रतिशत। कांग्रेस को 2.97 और वाममोर्चे को 4.45 प्रतिशत वोट मिले हैं। गैर बीजेपी वोटों को मिला दें तो यह आंकड़ा 49 प्रतिशत से ज्यादा हो जाता है। चुनावी राजनीति में सात प्रतिशत का अंतर बड़ा होता है। अब विपक्षी खेमे को लग रहा है कि अगर वे एक होते तो बीजेपी को ऐसी जीत नहीं मिलती। वैसे चुनावी गणित सामान्य गणित की तरह नहीं होता। 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस से बीजेपी को पांच लाख से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन सीटों के मामले में वह पिछड़ गई थी। चुनावी मैदान में जब सिर्फ दो खेमे होते हैं, तब मतदाताओं के बीच लंबवत ध्रुवीकरण हो जाता है। तब बिखराव वाले आंकड़े भी बदल जाते हैं। 2014 के संसदीय चुनाव में उत्तर प्रदेश में ऐसा साफ दिखा, जब बीजेपी सब पर भारी रही।

संसदीय चुनाव में सफलता के लिहाज से देखें तो कांग्रेस की 99 सीटों के बाद 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी विपक्ष का दूसरा बड़ा दल है। तीसरे नंबर पर 29 सीटों के साथ ममता ही हैं। इंडिया ब्लॉक की पहली बैठक के पीछे ममता का भी विचार था, फिर भी ना तो लोकसभा और ना ही विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस या ब्लॉक के दूसरे दलों को तवज्जो दिया। तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस की खींचतान जारी रही। विपक्ष के किसी भी दल ने एकता की कीमत पर त्याग स्वीकार नहीं किया। विपक्षी खेमे का संकट यह है कि वह अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में सहयोगियों से हिस्सेदारी बांटना ही नहीं चाहता।

मजबूत एकता के लिए विपक्ष के पास राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य साफ छवि वाला चेहरा होना जरूरी है। लेकिन विपक्ष के पास ऐसा चेहरा है भी नहीं। ममता बड़ी नेता तो हैं, लेकिन उनकी तुनकमिजाजी उन्हें सर्वमान्य चेहरा मानने के राह की बड़ी बाधा है। राहुल मोदी-शाह की जोड़ी को चाहे जिस अंदाज में चुनौती दें, मोदी विरोधी बौद्धिकों को उनका यह अंदाज चाहे जितना भी पसंद हो, लेकिन आमजन को उनमें कई बार बचकानापन नजर आता है तो कई मर्तबा प्रहसन।

आखिर सिस्टम पर हमले की प्रवृत्ति कितनी जायज या नाजायज है? चिंतन कीजिए

कमलेश पांडे

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के क्रम में याचिकाकर्ता की अपरिपक्व भाषा और समकालीन 'सिस्टम पर हमले की प्रवृत्ति' पर एक तल्ख टिप्पणी की और परजीवी तक कह डाला। लिहाजा इसको भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। हालांकि, यह टिप्पणी केवल न्यायपालिका तक सीमित नहीं है, बल्कि संसद, चुनाव आयोग, मीडिया, नौकरशाही और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार बढ़ते अविश्वास, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सोशल मीडिया आधारित आक्रामक विमर्श की ओर संकेत करती है।

इसलिए इसके अहम सियासी और प्रशासनिक मायने हैं और संविधान का संरक्षक होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय भी अपने नैतिक दायित्व से सिर्फ छिछली टिप्पणी करके बच नहीं सकता, क्योंकि उसे हासिल स्वतः संज्ञान का अधिकार भी गरीबों की भलाई में एक हदतक निरर्थक प्रतीत होता आया है। बावजूद इसके सीजेआई की टिप्पणी कई मायनों में जायज मानी जा सकती है, क्योंकि आज भारत सहित दुनिया के अनेक लोकतंत्रों में यह प्रवृत्ति बढ़ी है कि यदि किसी संस्था का निर्णय किसी राजनीतिक या वैचारिक समूह के पक्ष में नहीं जाता, तो पूरी संस्था की वैधता पर ही प्रश्नचिह्न लगा दिया जाता है। इससे संस्थागत विश्वास कमजोर होता है। लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, बल्कि संस्थाओं की विश्वसनीयता से भी चलता है।

मीडिया माध्यमों का अनुभव बताता है कि हाल के वर्षों में न्यायपालिका पर 'पक्षपात', चुनाव आयोग पर 'सरकारी प्रभाव', मीडिया पर 'प्रोपेगेंडा', और जांच एजेंसियों पर 'राजनीतिक उपयोग' जैसे आरोप लगातार तेज हुए हैं, जो दूसरी ओर, सत्ता पक्ष का तर्क रहता है कि कई बार आलोचना के नाम पर संस्थाओं को जानबूझकर बदनाम करने का अभियान चलाया जाता है। ऐसे माहौल में सीजेआई का यह कहना कि 'पूरे सिस्टम पर हमला' लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है, एक संतुलित चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है।

हालांकि, इस टिप्पणी का दूसरा स्याह पक्ष भी है। लोकतंत्र में संस्थाओं की आलोचना करना नागरिकों और विपक्ष का अधिकार है। यदि किसी संस्था के निर्णयों, कार्यशैली या पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं, तो उन्हें 'सिस्टम पर हमला' कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। चूंकि स्वस्थ लोकतंत्र में जवाबदेही और आलोचना दोनों जरूरी हैं। न्यायपालिका स्वयं कई ऐतिहासिक फैसलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति के अधिकार को लोकतंत्र का मूल तत्व बता चुकी है।

दरअसल समस्या तब पैदा होती है जब आलोचना तथ्यों और संवैधानिक बहस की जगह व्यक्तिगत हमलों, दुष्प्रचार, ट्रोलिंग या संस्थाओं को पूरी तरह अवैध बताने तक पहुंच जाती है। इससे जनता का भरोसा टूटता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। इसलिए सीजेआई की टिप्पणी को पूरी तरह गलत भी नहीं कहा जा सकता और इसे आलोचना-विरोधी बयान भी नहीं माना जाना चाहिए।

वस्तुतः इसका सार सत्य यह है कि संस्थाओं की आलोचना हो, लेकिन तथ्यों और संवैधानिक मर्यादा के साथ। असहमति हो, लेकिन लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करने वाली भाषा से बचा जाए। संस्थाएं भी पारदर्शिता, निष्पक्षता और आत्मसुधार बनाए रखें, ताकि जनता का विश्वास मजबूत रहे। लोकतंत्र में सबसे बड़ा संतुलन यही है कि संस्थाओं का सम्मान भी बना रहे और उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित होती रहे। जहां तक विद्रूप होती व्यवस्था के कड़वे सच से सामना की बात है तो बेरोजगार युवाओं के भीतर यह भावना तेजी से बढ़ती जा रही है कि व्यवस्था में अवसर समान नहीं हैं। जब भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, राजनीतिक संरक्षण, जातीय ध्रुवीकरण, क्षेत्रीय पक्षपात या आर्थिक प्रभाव की खबरें सामने आती हैं, तो स्वाभाविक रूप से निराशा और आक्रोश पैदा होता है। बांग्लादेश और नेपाल में हुई जेन-जेड क्रांति और नेतृत्व परिवर्तन के पीछे भी यही आरोप थे। यही कारण है कि कई युवा यह प्रश्न उठाते हैं कि यदि योग्यता के बजाय 'पहचान', 'संपर्क' या 'प्रभाव' ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, तो मेहनत और प्रतिभा का मूल्य क्या रह जाता है। आखिर ऐसी व्यवस्था को लोकतंत्र और संविधान की आड़ में कबतक झेला जाएगा?

लेकिन इस प्रश्न को संतुलन से समझना जरूरी है। चूंकि भारत जैसे विशाल और विविध समाज में कुछ नीतियां-जैसे- सामाजिक न्याय, आरक्षण, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व या कल्याणकारी योजनाएं-ऐतिहासिक असमानताओं को कम करने के उद्देश्य से बनाई गई थीं। लिहाजा, समस्या तब पैदा होती है जब इनका उपयोग वास्तविक सुधार के बजाय राजनीतिक लाभ, वोट बैंक या सत्ता-सुरक्षा के साधन के रूप में होने लगे। तब योग्य युवाओं को लगता है कि व्यवस्था निष्पक्ष नहीं है।

बहरहाल, आज बेरोजगार युवाओं की सबसे बड़ी पीड़ा केवल नौकरी की कमी नहीं, बल्कि 'समान अवसर पर भरोसे का संकट' है। उनकी शिकायतें मुख्यतः इन बिंदुओं पर केंद्रित हैं- भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षण और भाई-भतीजावाद, लंबे समय तक भर्तियों का अटकना, योग्यता की तुलना में पहचान आधारित लाभ का अनुभव, निजी क्षेत्र में भी नेटवर्क और प्रभाव की भूमिका और बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सीमित अवसर। लिहाजा, यह आक्रोश लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चेतावनी भी है। ऐसे में यदि युवाओं को लगे कि मेहनत का उचित प्रतिफल नहीं मिलेगा, तो सामाजिक असंतोष बढ़ सकता है। इसलिए किसी भी सरकार और व्यवस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह- भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनाए, पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई करे, कौशल आधारित रोजगार बढ़ाए, शिक्षा और उद्योग के बीच बेहतर तालमेल बनाए, अवसरों को अधिक निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धात्मक बनाए तथा सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मेरिट को मजबूत करे। साथ ही यह भी जरूरी है कि व्यवस्था की कमियों के खिलाफ आवाज लोकतांत्रिक और रचनात्मक तरीके से उठे। यद्यपि पूरे संविधान, लोकतंत्र या किसी समुदाय के खिलाफ घृणा पैदा करना समाधान नहीं बनता। बल्कि वास्तविक सुधार संस्थागत दबाव, जन-जागरूकता, न्यायिक हस्तक्षेप, पारदर्शिता और राजनीतिक जवाबदेही से आता है। चूंकि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा आबादी है। यदि यही वर्ग व्यवस्था से पूरी तरह निराश हो जाए, तो यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संकट भी बन सकता है। इसलिए 'योग्यता आधारित अवसर' और 'सामाजिक न्याय'- दोनों के बीच संतुलन बनाना आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती होगी।

नीट परीक्षा की समस्या ज्यादा गहरी है

अजीत द्विवेदी

मेडिकल में दाखिले के लिए इस साल तीन मई को हुई नीट यूजी की परीक्षा रद्द कर दी गई है और पेपर लीक की सीबीआई जांच चल रही है। इस बात का चौतरफा शोर है कि जबरदस्त जांच चल रही है। दस लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुणे का एक केमिस्ट्री शिक्षक पीवी कुलकर्णी मास्टरमाइंड है। पुणे की ही बायोलॉजी की शिक्षक मनीषा मंधारे भी शामिल है। पुणे का कोचिंग संचालक भी गिरफ्तार हो गया है, जिसे दस दिन पहले ही पेपर मिल गया था। यह भी कहा जा रहा है कि राजस्थान में सीकर का आदमी शामिल है तो चुरू का व्यक्ति भी शामिल है। अच्छी बात है कि सीबीआई जांच कर रही है और पेपर लीक करने वालों को पकड़ रही है। लेकिन क्या इससे जिन 23 लाख छात्रों का पेपर रद्द हुआ है उनको कोई लाभ होगा?

और दूसरा सवाल यह है कि दोबारा परीक्षा होगी तो क्या इस बात की गारंटी हो जाएगी की उसमें पेपर लीक या दूसरी कोई गड़बड़ी नहीं होगी? यह भी सवाल है कि जिन बच्चों ने तीन मई को बहुत अच्छा पेपर दिया था 21 जून को उनका पेपर खराब होता है तो इस अपराध का दोषी कौन होगा? जहां तक पेपर लीक और सीबीआई जांच की बात है तो 2024 के नीट यूजी में भी पेपर लीक हुआ था और कई जगह परीक्षा केंद्र मैनेज करके सॉल्वर गैंग ने चुनिंदा छात्रों की परीक्षा कराई थी। उसमें भी कुछ केंद्रों पर परीक्षा रद्द हुई और सीबीआई ने जांच की। लेकिन फिर एक साल के बाद 2026 में पेपर लीक हो गया। हैरानी की बात है कि 2024 के जून में पेपर लीक और परीक्षा केंद्रों पर धांधली की जांच सीबीआई ने शुरू की और जनवरी 2025 में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। पिछले हफ्ते खबर आई कि दिल्ली की एक अदालत ने इस पर नाराजगी जताई है।

सोचें, उस जांच से क्या निकला और क्या हासिल हुआ? बिहार के जिस संजीव मुखिया को मास्टरमाइंड बताया गया था उसके खिलाफ आरोपपत्र तक दाखिल नहीं हुआ। इसलिए यह कोई समाधान नहीं है। पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द हो गई यह सचाई है। उसके बाद सीबीआई कुछ भी करे उससे बच्चों के भविष्य पर कोई असर नहीं होता है। यह सिर्फ नैरेटिव बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छोटी छोटी बातों को बड़ा बना कर दिखाया जाता है कि देखो, मास्टरमाइंड पकड़ लिया, दस लोग पकड़ लिए, दस शहरों में छापे मारे।

शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं कि दोबारा परीक्षा की फीस नहीं लगेगी या परीक्षार्थियों की आवाजाही की व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों से बात करेंगे यह भी एक बड़े जख्म पर बैंडएड लगाने जैसा है। इन सब बातों से कुछ नहीं होता है। पिछली बार पेपर लीक का एपिसेंटर बिहार, झारखंड, गुजरात और हरियाणा था तो इस बार महाराष्ट्र और राजस्थान है। अगली बार हो सकता है कि कोई और राज्य हो। जिन नौ या दस लोगों को गिरफ्तार किया गया है इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अगली बार नए लोग आ जाएंगे। नया सॉल्वर गैंग खड़ा हो जाएगा।

असल में समस्या स्ट्रक्चरल है और उपाय साइकिकल हो रहे हैं। जनभावना के हिसाब से उपाय बताए जा रहे हैं। सरकार गैलरी के लिए खेलती दिख रही है। शिक्षा मंत्री ने लोगों को खुश करने के लिए कह दिया कि अगले साल से परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी। यानी जैसे इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए जेईई मेन्स की परीक्षा होती है वैसी परीक्षा नीट की होगी। यह अच्छी बात है। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा यानी सीबीटी में फिजिकल प्रश्न पत्र कहीं लाने ले जाने की जरुरत नहीं पड़ती है और इससे लीक होने का एक रास्ता बंद होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह उपाय फुलप्रूफ है। अगर प्रश्न पत्र तैयार करने वाला ही पेपर लीक करे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कि परीक्षा पेन और पेपर से हो रही है या कंप्यूटर पर हो रही है?

इसी बार पेपर लीक करने वाले वो लोग हैं, जो पेपर तैयार करने वाली कमेटी में शामिल थे। वैसे भी पहले कई परीक्षाओं में सीबीटी के बावजूद पेपर लीक हुआ। जेईई मेन्स 2021 में विदेशी सर्वर के जरिए सिस्टम हैक करने की घटना हुई थी। 2018 में रेलवे भर्ती परीक्षा में या उससे पहले 2017 में एसएससी की परीक्षा में सीबीटी के बावजूद गड़बड़ी हुई। समस्या सिर्फ पेपर लीक नहीं है। सॉल्वर गैंग परीक्षा केंद्र मैनेज करता है और कई बार डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाई जाती है। इसके अलावा जब सीबीटी की परीक्षा होगी तो कई पालियों में परीक्षा होगी और उसके बाद अंकों के सामान्यीकरण का खेल शुरू होगा, जिसमें स्वाभाविक रूप से बच्चों के साथ अन्याय होने की संभावना रहती है।

सो, अगर सरकार सचमुच ईमानदार है और परीक्षा प्रणाली की खामियों को दूर करके इसे फुलप्रूफ बनाना चाहती है तो उसे ढांचागत बदलाव करने होंगे। सबसे पहले तो एक देश, एक परीक्षा की जिद छोड़नी होगी। चौथाई करोड़ छात्रों की परीक्षा एक बार में कराना कभी भी बहुत सुरक्षित विकल्प नहीं हो सकता है। वैसे भी भारत जैसे क्षेत्रीय, भाषायी और भौगोलिक विविधता वाले देश में डॉक्टर बनाने के लिए एक परीक्षा कराना उचित नहीं है। इसको विकेंद्रित करना चाहिए। राज्यों को अपने मेडिकल कॉलेजेज में दाखिले की परीक्षा कराने या वैकल्पिक व्यवस्था करने की छूट देनी चाहिए।

केंद्रीय संस्थानों में दाखिले की परीक्षा केंद्र सरकार की एजेंसी कराए। दूसरा उपाय यह है कि परीक्षा कराने वाले केंद्रीय निकाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को दुरुस्त करना होगा। इसे वैधानिक निकाय बना कर, इसका अपना कैडर तैयार करना होगा। इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करनी होगी। पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई का जो कानून बनाना है उसका दायरा परीक्षा कराने वालों तक लाया जाना चाहिए।

स्ट्रक्चरल उपाय के तहत ही मेडिकल में दाखिले की परीक्षा को ह्यहाई स्टेकह्ल परीक्षा की बजाय सामान्य दाखिला परीक्षा बनाना होगा। इसके लिए जरूरी है कि मेडिकल की पढ़ाई को सस्ता किया जाए। भारत में मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है। चार साल की पढ़ाई की फीस एक करोड़ रुपए से ज्यादा है। ऊपर से ज्यादातर निजी कॉलेजों में अब भी डोनेशन लेने का चलन है। वह किसी न किसी रूप में देना पड़ता है। सरकारी मेडिकल कॉलेज बहुत कम हैं। इसलिए लोगों को निजी कॉलेजों की तरफ ही देखना होता है। सो, लाखों लाख रुपए की डोनेशन और ऊपर से करोड़ों की फीस की चिंता में अभिभावक पेपर लीक कराने वालों या परीक्षा केंद्र मैनेज करने वालों के झांसे में आते हैं। अगर पढ़ाई सस्ती हो जाए तो काफी कुछ ठीक हो सकता है।

अंत में सबसे ज्यादा जरुरत ईमानदारी की है। परीक्षा कराने की व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों, पेपर तैयार करने वाले शिक्षकों और परीक्षा केंद्रों पर काम करने वालों से न्यूनतम ईमानदारी की उम्मीद की जाती है। इसके बगैर सारे उपाय विफल हो जाएंगे।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक पुरुषोत्तम पाण्डेय द्वारा मौनेक्स ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, बी-12, निकट एमएमजी अस्पताल, शंभू दयाल काम्पलेक्स, जीटी रोड, गाजियाबाद से मुद्रित एवं 498 प्रथम तल, मैत्री लेन, सैक्टर-5, वैशाली गाजियाबाद से प्रकाशित।

सम्पादक : विजय प्रकाश पाठक
Mob : 9910460742
RNI No. : UPHIN/2022/84480
website : www.swastiksahara.com
E-mail : swastiksaharanews@gmail.com

विधि सलाहकार
टेट्रा लीगल एलएलपी, लॉ फर्म, नई दिल्ली
मो. नं.: +91 99990 74369
ओमीलाल वर्मा (एडवोकेट)
मो. नं.: 98109 03664

City Office:
11, Maliwara, Near Pyarelal Park, Vasant Road,
Ghaziabad-201001Phone : 0120-4252839

डस्ट प्रदूषण पर सख्त हुए जिलाधिकारी, प्रदूषण फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

डाला, ओबरा और अनपरा में प्रतिदिन चलेगी स्मोक गन

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

सोनभद्र। जनपद में बढ़ते डस्ट प्रदूषण को लेकर जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने सख्त रुख अपनाया है। डस्ट नियंत्रण एवं प्रदूषण निस्तारण को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में विशेष रूप से डाला, ओबरा और अनपरा क्षेत्र में बढ़ते धूल प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए व्यापक अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि नगर पंचायत डाला, ओबरा एवं अनपरा के अधिक धूल प्रभावित क्षेत्रों में स्मोक गन के माध्यम से प्रतिदिन नियमित रूप से पानी का छिड़काव कराया जाए। उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक तथा शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक संचालित किया जाए, ताकि आमजन को धूल और प्रदूषण से राहत मिल सके। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों के किनारे उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए नियमित साफ-सफाई, पानी का छिड़काव तथा निर्माण कार्यों में प्रदूषण नियंत्रण मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए।

जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नगर पंचायतों द्वारा कराए जा रहे छिड़काव कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, जिससे जनपदवासियों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जनपद में संचालित कंपनियों और क्रशर प्लांटों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जो कंपनियां या क्रशर प्लांट अत्यधिक प्रदूषण फैलाते पाए जाएं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जिलाधिकारी ने फ्लाई ऐश को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि सड़कों के किनारे कहीं भी अनाधिकृत रूप से फ्लाई ऐश फेंकी हुई पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वागीश कुमार शुक्ला, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी आर.के. सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का प्रांतीय प्रतिनिधि कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ सम्पन्न

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नई दिल्ली। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद दिल्ली प्रदेश द्वारा आज 'प्रांतीय प्रतिनिधि कार्यकर्ता सम्मेलन' का आयोजन इंजीनियर्स भवन आईटीओ में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ सुमंत गुप्ता ने की। उन्होंने संस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में बताते हुए सभी से आग्रह किया 21 जून से 29 जून तक चलने वाली जन संदेश यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। 29 जून को होने वाली राष्ट्र भक्त भामा शाह की जयंती को भव्य रूप से मनाया जाये और प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग रोका जाए। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राज कुमार गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए आवाहन को जन जन तक पहुंचाया जाए और राजनीतिक भागीदारी बढ़ा कर समाज को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलवाया जाए। राष्ट्रीय प्रभारी डॉ. हरिओम अग्रवाल, प्रधान महासचिव अमित वार्ष्णेय, प्रदेश महासचिव प्रीतम गुप्ता, महासचिव ओम प्रकाश पोरवाल एवं डॉ वी के गुप्ता खोरा ने भी वैश्य समाज की एकता एवं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने विचार रखे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुधीर चन्द्र पोरवाल ने कहा कि देश या प्रदेश में वैश्य समाज का ऐसा कोई नेता नहीं है जो वैश्य समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर आए संकट या किसी के द्वारा यदि अत्याचार किया गया हो उस समय यह कह सके कि मैं वैश्य समाज का हूं और वैश्य समाज के साथ हूं। यदि इसके साथ न्याय नहीं किया जाता है तो में अपने पद से त्याग पत्र देकर धरना प्रदर्शन कर सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करूंगा। इस बैठक में भारी संख्या में पदाधिकारियों ने भाग लिया।कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रभक्त शिरोमणि भामाशाह, महाराजा टोडरमल और महाराजा अग्रसेन के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ और उसके बाद सभी का अंग वस्त्र पहनाकर सम्मान किया गया।

बकरीद को लेकर पीस कमेटी की बैठक सम्पन्न,गाइडलाइंस की दी जानकारी

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

परसपुर गोण्डा। स्थानीय थाना परिसर में आगामी बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से बुधवार को पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तथा क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। इस दौरान थानाध्यक्ष कमल शंकर चतुर्वेदी ने लोगों से आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूर्णतया रोक है तथा सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी कदापि न करें। साथ ही साफ-सफाई एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुये अवशेषों को निश्चित स्थान पर ही दफन करने के निर्देश दिए। थानाध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ, आपत्तिजनक अथवा अफवाह फैलाने वाली पोस्ट साझा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उन्होंने उपस्थित सभी वरिष्ठ नागरिकों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज विनय कुमार सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष वासुदेव सिंह, सऊद खान, साकिर खान, शरीफ, सोएब आदि रहे।

हरतीरथ कांड में कोर्ट का बड़ा आदेश: व्यवसायी से मारपीट, लूटपाट और तोड़फोड़ मामले में हिन्दू युवा वाहिनी से जुड़े लोगों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

वाराणसी। हरतीरथ क्षेत्र में दुकान कब्जाने के विरोध पर व्यवसायी के साथ मारपीट, लूटपाट और तोड़फोड़ के मामले में अदालत ने बड़ा आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (नवम) अमित कुमार यादव की अदालत ने कोतवाली थाना प्रभारी को हिन्दू युवा वाहिनी से जुड़े लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

यह आदेश हरतीरथ निवासी मुकुंद यादव द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया गया। वादी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव और धनंजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के तहत अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि हरतीरथ चौराहे पर मुकुंद यादव की तीन दुकानें हैं, जिनसे उनके परिवार का भरण-पोषण होता है। आरोप है कि उमेश सिंह और मुकेश सिंह उनकी एक दुकान पर जबरन कब्जा करना चाहते थे। दुकान देने से इनकार करने पर उन्हें धमकी दी गई कि किसी भी कीमत पर दुकान कब्जे में लेकर रहेंगे। वादी के अनुसार 18 मार्च 2026 की शाम करीब चार बजे उमेश सिंह, मुकेश सिंह, कुणाल सिंह उर्फ गोलू तथा हिन्दू युवा वाहिनी से जुड़े 12 से 15 अज्ञात समर्थक जबरन उनके मकान में घुस आए। आरोप है कि सभी ने मिलकर बिल्डिंग मैटेरियल के सामान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर व्यवसायी के साथ मारपीट की गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।

प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि हमलावर दुकान में रखा कीमती सामान भी उठा ले गए और घटना में लगभग डेढ़ लाख रुपये का नुकसान हुआ। पीड़ित पक्ष का कहना है कि घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई थी, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। उल्टे विपक्षी पक्ष की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली पुलिस ने मुकुंद यादव के खिलाफ ही विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और तथ्यों का अवलोकन किया। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों को प्रथम दृष्टया पर्याप्त मानते हुए कोतवाली थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अदालत के इस आदेश के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। क्षेत्र में इस प्रकरण को लेकर चचाओं का दौर तेज हो गया है और अब सभी की नजर पुलिस की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।

आईआईटी कानपुर में एमटेक में चयनित हुए चंद्रकांत त्रिपाठी, क्षेत्र का बढ़ाया मान

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

परसपुर, गोण्डा। विकास खंड परसपुर क्षेत्र के छतौनी निवासी चंद्रकांत त्रिपाठी ने प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के स्पेस, प्लेनेटरी एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में एमटेक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाकर क्षेत्र एवं परिजनों का गौरव बढ़ाया है। उनकी इस उपलब्धि से गांव व क्षेत्र में खुशी का माहौल है। चंद्रकांत के चचेरे भाई एवं परिषदीय विद्यालय के शिक्षक कमलापति त्रिपाठी ने बताया कि चंद्रकांत बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं। हाईस्कूल के दौरान उन्होंने मैथमेटिक्स ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। उन्होंने बताया कि गेट-2026 परीक्षा में एआईआर 7970 रैंक प्राप्त कर चंद्रकांत ने आईआईटी कानपुर में एमटेक प्रवेश के लिए अपना स्थान सुनिश्चित किया। चंद्रकांत ने आंध्रप्रदेश के एक निजी कॉलेज से कंप्यूटर साइंस (सीएस) में बीटेक की शिक्षा प्राप्त की है। उनके पिता किसान हैं जबकि माता गृहिणी हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद चंद्रकांत की मेहनत और लगन ने उन्हें यह सफलता दिलाई है। इस अवसर पर कुलदीप सिंह, अशोक पांडेय, संतोष पांडेय, इंद्रप्रताप सिंह, कृष्णकुमार त्रिपाठी, विपिन सिंह, शिवेंद्र सिंह, अमित सिंह सहित क्षेत्र के तमाम लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

किसानों की महापंचायत का हुआ असर, प्रशासन ने दिया 10 दिन में ठेका हटाने का आश्वासन

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

दनकौर। आज सालेपुर दनकौर में शराब के ठेके के विरोध में भारतीय किसान यूनियन बलराज संगठन के बैनर तले एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत के उपरांत संगठन के सैकड़ों कार्यकताओं व ग्रामीणों ने एकजुट होकर शराब के ठेके पर पहुंचकर उसे तत्काल प्रभाव से बंद कराया। विरोधस्वरुप कार्यकताओं ने ठेके पर संगठन का बैनर लगाकर धरना शुरू कर दिया। मौके की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी दनकौर, आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर एवं एडीसीपी ग्रेटर नोएडा स्वयं धरना स्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने उपस्थित ग्रामवासियों व संगठन के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि 10 दिन के भीतर इस शराब के ठेके को यहां से बंद कर अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाएगा।प्रशासन के इस आश्वासन के बाद ही संगठन के पदाधिकारी व ग्रामीण शांत हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा रेखा सिवल ने कहा कि गांव के बीचों-बीच शराब का ठेका हमारी बहन-बेटियों की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि 10 दिन में यह ठेका बंद नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन बलराज संगठन आर-पार की लड़ाई लड़ेगा और अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता विपिन खारी ने कहा कि एडीसीपी ग्रेनो को अवगत करा दिया गया है कि स्थानीय चौकी इंचार्ज की कार्यशैली में भारी कमियां हैं। यदि उन्होंने अपनी कार्यप्रणाली नहीं सुधारी तो संगठन उनके खिलाफ भी मोर्चा खोलने को बाध्य होगा। संगठन ने स्पष्ट किया है कि वह गांव की शांति और युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए हर संघर्ष को तैयार है। आज की महापंचायत में संगठन के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

अज्ञात वाहन की चपेट में आकर युवक की मौत

परसपुर गोण्डा। थाना क्षेत्र परसपुर अंतर्गत परसपुर-करनैलगंज सीबीएन मार्ग पर आटा में धर्म कांटा के पास बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का जिला अस्पताल गोण्डा में उपचार चल रहा है। ग्राम आटा के मजरा पंडित सिवान निवासी रोज अली ने पुलिस को तहरीर देकर अवगत कराया है कि उनका साला समीर बाइक से गैस सिलेंडर लाने परसपुर जा रहा था। उसके साथ कुन्ने भी बाइक पर सवार थे। जैसे ही दोनों युवक आटा धर्म कांटा के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रहे वाहन ने टक्कर मार दी।इस दौरान समीर के सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुन्ने गंभीर रूप से घायल हो गया। थानाध्यक्ष कमलशंकर चतुर्वेदी ने बताया कि घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवाया।

खरीफ अभियान-2026 हेतु सहकारी समितियों पर उर्वरक उपलब्धता बढ़ाई गई

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

सोनभद। जनपद सोनभद्र के किसान भाइयों को खरीफ अभियान-2026 के दौरान उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की संस्तुति के उपरांत दिनांक 05 मई 2026 को जनपद की 41 सहकारी समितियों में कुल 769.500 मीट्रिक टन यूरिया तथा दिनांक 20 मई 2026 को 05 सहकारी समितियों में कुल 121.000 मीट्रिक टन पीपीएल फास्फेटिक उर्वरक के आवंटन को अनुमोदन प्रदान किया गया है। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, सोनभद्र ने अवगत कराया कि आवंटित उर्वरकों के सापेक्ष पीसीएफ द्वारा सहकारी समितियों एवं उर्वरक बिक्री केंद्रों पर उर्वरक भेजने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है, जिससे किसानों को समय से उर्वरक उपलब्ध हो सके।

कृषक बंधुओं से अपील की गई है कि वे अपने निकटतम सहकारी समिति अथवा उर्वरक केंद्र से संपर्क कर उर्वरकों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करें तथा निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरक खरीदें। यदि कहीं कालाबाजारी, ओवररेटिंग अथवा कृत्रिम अभाव की शिकायत मिले तो तत्काल सहकारिता विभाग के कंट्रोल रूम मोबाइल नंबर 9198788248, 9451637073 अथवा जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के मोबाइल नंबर 9452165778 एवं अपर जिला कृषि अधिकारी के मोबाइल नंबर 8881173660 पर सूचना दें, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

भू-माफियाओं के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कारवाई, पांच हजार वर्गमीटर जमीन कब्जा मुक्त

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। भू-माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कारवाई करते हुए नोएडा प्राधिकरण ने बुधवार को ग्राम सोरखा जाहिदाबाद के अधिसूचित क्षेत्र में करीब 5 हजार वर्गमीटर जमीन को कब्जामुक्त करवाया। इस दौरान कुछ लोगों ने प्राधिकरण की इस कार्रवाई का विरोध करने का प्रयास किया लेकिन पुलिस बल को देखकर भाग गए। कार्यवाही से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आरोप हैं कि अतिक्रमणकारियों को पहले दो बार नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। बताते चले कि प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश के निर्देश पर भूलेख विभाग, वर्क सर्किल-6 और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने जेसीबी मशीनों की मदद से ग्राम सोरखा जाहिदाबाद के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध प्रीकास्ट बाउंड्रीवाल और गेट को ध्वस्त किया। बताया गया कि भूमाफियाओं ने प्लॉटिंग के उद्देश्य से जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। कार्रवाई के दौरान लगभग 80 कर्मचारियों और पुलिस बल की मौजूद रहे।अधिकारियों के अनुसार अतिक्रमणकारियों को पहले दो बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उन्होंने जन सामान्य को सचेत किया है कि इस तरह की भूमि पर हो रहे प्लाटिंग में खरीद-फरोख्त के लिए भू माफियाओं के चंगुल में न आएं। नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में बिना अनुमति या फिर बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि अधिसूचित क्षेत्र में जमीन खरीदने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें और अवैध कॉलोनियों या प्लॉटिंग के झांसे में न आएं। बिना अनुमति या नक्शा पास कराए निर्माण करने

बड़े डॉग शेल्टर बनाने की योजना जमीन चिन्हित करने तक अटकी

नोएडा। लावारिस कुत्तों के संबंध में नवंबर, 2025 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शहर में एक-एक हजार क्षमता के दो डॉग शेल्टर बनाने की प्रक्रिया नोएडा प्राधिकरण ने शुरू की थी। इसके लिए सेक्टर-123 और 93बी में जमीन भी चिन्हित कर ली गई थी लेकिन तब से इसमें कोई प्रगति नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बस अड्डा, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल व अन्य सार्वजनिक जगहों से लावारिस कुत्तों को हटाकर शेल्टर में रखना है। नए आदेश में भी कोर्ट ने पुराने आदेश को ही बरकरार रखा है। शहर में छोटे डॉग शेल्टर तो हैं लेकिन आगे कुत्तों की संख्या बढ़ने पर बड़े डॉग शेल्टर का निर्माण करने की तैयार थी। अभी प्राधिकरण आक्रामक कुत्तों को 15 दिन तक शेल्टर में रखकर वापस वहीं पर छोड़ देता है। नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-34, 94 में डॉग शेल्टर बनवा रखे हैं। यहां कट्खने कुत्तों को रैबीज लगाने से लेकर नसबंदी की जाती है।

अवैध शराब तस्करी पर पिपरी पुलिस का बड़ा प्रहार

वाहन समेत करीब 5 लाख रुपये की अंग्रेजी शराब बरामद, तीन तस्कर गिरफ्तार

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में जनपद में मादक पदार्थों एवं अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पिपरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पिपरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बरामद शराब और वाहन की कुल अनुमानित कीमत लगभग पांच लाख रुपये बताई जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अनिल कुमार के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी पिपरी हर्ष पाण्डेय के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष राजेश चौबे के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में चेकिंग एवं गश्त अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि रनटोला क्षेत्र से एक संदिग्ध कार के माध्यम से अवैध शराब की खेप ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर फिएट कार संख्या बीआर01एएस8250 को रोक लिया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस ने मौके से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि अभियुक्त मध्य प्रदेश से शराब लाकर बिहार में ऊंचे दामों पर बेचने के उद्देश्य से परिवहन कर रहे थे। पुलिस द्वारा बरामदगी के आधार पर थाना पिपरी में मु0अ0सं0-93/2026 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही बरामद वाहन को धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज कर दिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय भेज दिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में गोलू कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी सोभी चक थाना पिपरा जनपद पलामू झारखंड, जय प्रकाश कुमार पुत्र विजय कुमार सिंह निवासी पिठौरा थाना पिपरा जनपद पलामू झारखंड तथा हंशराज कुमार पुत्र तारा सिंह निवासी बेनीगढ़ थाना टडवा जनपद औरंगाबाद बिहार शामिल हैं।

बरामदगी में 14 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब शामिल है, जिसमें आइकॉनिक व्हाइट, रॉयल स्टैग, ब्लेंडर्स प्राइड और सिग्नेचर प्रीमियर ग्रेन व्हिस्की के विभिन्न ब्रांड शामिल हैं। कुल लगभग 121.860 लीटर शराब बरामद की गई है। इसके अलावा एक फिएट कार और तीन एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी पुलिस ने कब्जे में लिए हैं। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष राजेश चौबे, उपनिरीक्षक जितेन्द्र सरोज, हेड कांस्टेबल राजेश पासवान, मोहन खरवार, शिवबदन राम, रामजीत यादव तथा कांस्टेबल अजीत कुमार और कृष्णा यादव शामिल रहे।

विकास कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं: योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना की समीक्षा की

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, मंत्री एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में मानक, गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास प्रस्ताव तैयार कर एक सप्ताह के अंदर भेजा जाए, जून के प्रथम सप्ताह में कार्ययोजना को शासन से स्वीकृति मिल जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करें और विकास योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रूप दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं शिलान्यास संबंधित जनप्रतिनिधियों के कर कमलों से ही कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विभागीय कमियों अथवा ठेकेदारों की गलतियों का दायित्व जनप्रतिनिधियों का नहीं है। विकास कार्यों की गुणवत्ता और निर्धारित समय में कार्यों को पूर्ण कराना विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कनेक्टिविटी और मजबूत अवस्थापना किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति की जीवनरेखा होती है। सड़क, पुल और संपर्क मार्ग केवल आवागमन के साधन नहीं होते, बल्कि वे व्यापार, रोजगार और सामाजिक विकास को गति देने का माध्यम भी बनते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रस्ताव तैयार करते समय 'पिक एंड चूज' की प्रवृत्ति से बचा जाए और हर क्षेत्र की आवश्यकता को समान महत्व दिया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में संचालित प्रत्येक परियोजना के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो नियमित रूप से कार्य की प्रगति की निगरानी करे और गुणवत्ता सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष स्वीकृत परियोजनाओं की समीक्षा कर उनकी प्रगति रिपोर्ट समय पर शासन को भेजी जाए। साथ ही लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक जनपद में अलग से टीम भेजकर कार्यों का स्थलीय निरीक्षण और स्वतंत्र समीक्षा कराई जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने आपात परिस्थितियों के दृष्टिगत हेलीपैड निर्माण को भी आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा, स्वास्थ्य आपातकाल अथवा अन्य संकट की स्थिति में हेलीपैड अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसके मद्देनजर प्रत्येक ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय के निकट हेलीपैड बनाए जाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि इनके रखरखाव की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग निभाए और इनके प्रयोग के लिए निर्धारित शुल्क व्यवस्था भी विकसित की जाए। मुख्यमंत्री ने वैश्विक परिस्थितियों के कारण ईंधन एवं बिटुमेन की उपलब्धता पर पड़ रहे प्रभाव का उल्लेख करते हुए लोक निर्माण विभाग को तकनीकी नवाचार अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बदलती परिस्थितियों के अनुरूप विभाग को कार्यप्रणाली में व्यावहारिक सुधार लाने होंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि दो किलोमीटर तक के ग्रामीण मार्गों पर आवश्यकता अनुसार गुणवत्तापूर्ण सीसी रोड का निर्माण कराया जाए। साथ ही बिटुमेन की खपत कम करने के लिए जीएसबी के स्थान पर सीटीएसबी (सीमेंट ट्रीटेड सबबेस) तथा डब्ल्यूएमएम के स्थान पर सीमेंट ट्रीटेड बेस तकनीक को प्राथमिकता से अपनाया जाए, ताकि सड़क निर्माण अधिक टिकाऊ और किफायती बन सके। मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग की ह्लसीएम ग्रिडह्व योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह शहरी कनेक्टिविटी को मजबूत करने की महत्वपूर्ण पहल है, लेकिन इसकी गति और तेज करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग स्थानीय जरूरतों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करे और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश के प्रत्येक मोहल्ले और कॉलोनी तक बेहतर सड़क और संपर्क व्यवस्था पहुंचे। बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग की ओर से विस्तृत प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि विभाग के 17 मदों के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए अब तक 30,000 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी प्रस्तावों की प्राथमिकता तय कर योजनाओं को चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा जाए, ताकि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

नक्सल गतिविधियों पर सतर्कता बढ़ाने को लेकर समन्वय गोष्ठी आयोजित

अपर पुलिस अधीक्षक ने सीमावर्ती जनपदों के अधिकारियों संग सुरक्षा व्यवस्था और संयुक्त अभियान पर की विस्तृत समीक्षा

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

सोनभद्र। पुलिस लाइन चुर्क स्थित सभागार कक्ष में अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ऋषभ रुणवाल की अध्यक्षता में नक्सल समन्वय गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में जनपद पुलिस, पीएसी, विभिन्न विभागों तथा सीमावर्ती जनपद मीरजापुर और चंदौली से आए अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। गोष्ठी के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने, आपसी समन्वय बढ़ाने तथा संयुक्त रणनीति के तहत अभियान चलाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में नक्सली गतिविधियों एवं संभावित संचरण को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ने कहा कि विभिन्न जनपदों एवं सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर नियमित रूप से कॉम्बिंग एवं एरिया डोमिनेशन अभियान चलाए जाएं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान के दौरान स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए तथा उनका त्वरित और प्रभावी समाधान कराया जाए। ग्रामीणों के साथ लगातार संवाद स्थापित कर उन्हें जागरूक किया जाए कि वे किसी के बहकावे में न आएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन को दें। गोष्ठी में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने, खुफिया तंत्र को सक्रिय रखने, सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त अभियान चलाने तथा जनसहभागिता बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी बनाए रखने और सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने पर भी जोर दिया। बैठक में क्षेत्राधिकारी यातायात डॉ. चारु द्विवेदी, डिप्टी सीएमओ डॉ. शैलेन्द्र, प्रभारी निरीक्षक जोनल नक्सल अभिसूचना इकाई राणा प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक स्थानीय अभिसूचना इकाई महेन्द्र प्रताप यादव, कम्पनी कमाण्डर 48वीं आईआर वाहिनी मनोज कुमार सहित नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक ने सुनीं आमजन की समस्याएं

त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी निस्तारण के दिए निर्देश, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा द्वारा पुलिस कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई एवं जनता दर्शन कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना गया। कार्यक्रम के दौरान भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, मारपीट, गुमशुदगी, साइबर धोखाधड़ी, राजस्व प्रकरणों तथा अन्य पुलिस संबंधी मामलों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुईं। पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक प्रकरण का स्वयं संज्ञान लेते हुए संबंधित क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को न्याय दिलाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी पीड़ित को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक ने निर्देशित किया कि सभी शिकायतों की तथ्यपरक एवं गुणवत्तापूर्ण जांच की जाए तथा पीड़ित पक्ष को की गई कार्रवाई से समय-समय पर अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है, उनमें बिना विलंब विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनावश्यक देरी या उत्पीड़न की शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि जनता से संवाद बेहतर बनाए रखें और शिकायतकर्ताओं के साथ संवेदनशील व्यवहार करें। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने कहा कि जनसुनवाई कार्यक्रम पुलिस और जनता के बीच विश्वास एवं पारदर्शिता मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है। आमजन की समस्याओं का त्वरित, निष्पक्ष और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करना पुलिस प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, भूमि विवाद और पारिवारिक मामलों में विशेष सतर्कता बरतते हुए समयबद्ध कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके और कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों की लाइव ट्रैकिंग से सुरक्षित बनाया जा रहा यात्रियों का सफर

प्रतिदिन 16 लाख से ज्यादा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही योगी सरकार

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने और यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास करती आ रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) यात्रियों को सुरक्षित, सुगम यात्रा का अनुभव देने के लिए बड़े पैमाने पर नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। यूपीएसआरटीसी की लगभग सभी बसों की लाइव ट्रैकिंग हो रही है, ताकि प्रतिदिन इन बसों में सफर करने वाले 16 लाख से अधिक यात्रियों की सुरक्षा पुख्ता की जा सके। यूपीएसआरटीसी के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए 13,500 से अधिक बसों को व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) से जोड़ा जा चुका है। इसकी ट्रैकिंग लखनऊ स्थित मुख्यालय के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हो रही है।

बस ड्राइवरों की जवाबदेही भी तय की गई

उन्होंने बताया कि इन बसों में प्रतिदिन 16 लाख से अधिक लोग यात्रा कर रहे हैं। बसों की ट्रैकिंग के लिए हर रोज 24 घंटे मुख्यालय का कमांड सेंटर और 20 रीजनल मॉनिटरिंग सेंटर एक्टिव रहते हैं। यहां से बस की ओवर स्पीड, तेज ब्रेक लगाने, तेज गति में बस मोड़ने, तय सीमा से अधिक रफ्तार पर बस चलाने, तय रूट समेत अन्य पर नजर रखी जा रही है। इसकी मुख्यालय से रोज रिपोर्ट तैयार होती है और गलती पाए जाने पर बस ड्राइवर को चेतावनी या कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। इससे प्रदेश में दुर्घटनाओं में काफी कमी लाई जा रही है। लाइव ट्रैकिंग के साथ इन बसों में हादसे या आपात स्थिति के लिए पैनिक बटन भी लगाए गए हैं। इनका इस्तेमाल होते ही अलर्ट यूपीएसआरटीसी कमांड सेंटर के साथ यूपी पुलिस के कंट्रोल रूम को भी जाता है। इसके बाद फौरन कंडक्टर से संबंधित विभागों द्वारा बात कर उचित एक्शन लिया जाता है। यूपीएसआरटीसी के मुताबिक हर रोज 5 हजार से अधिक अलर्ट आते हैं। जरूरत के हिसाब से मदद उपलब्ध कराई जाती है। यूपीएसआरटीसी के मार्गदर्शी पोर्टल और निगम की वेबसाइपट पर ट्रैक माई बस के जरिए यात्रियों को काफी सुविधा मिल रही है। यात्री बस की लोकेशन कहीं से भी लाइव देख सकते हैं।

परिषदीय और केजीबीवी में इनोवेशन कल्चर विकसित करेगी योगी सरकार

विद्यालयों में संगोष्ठी, टेक्नोलॉजी आधारित विशेष कक्षाएं, क्विज और निबंध प्रतियोगिताएं होंगी आयोजित

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

लखनऊ। योगी सरकार परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ-साथ देश के उभरते इनोवेशन और तकनीकी बदलावों से जोड़कर भविष्य के लिए तैयार करने में जुट गई है। 'भारत इनोवेट्स 2026' अभियान के माध्यम से पहली बार गांव और कस्बों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को डीप टेक्नोलॉजी, रिसर्च, नवाचार और वैज्ञानिक सोच से जोड़ने की बड़ी पहल शुरू की गई है। योगी सरकार का लक्ष्य है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े बच्चे तक भी वही आधुनिक सीखने का माहौल पहुंचे, जो अब तक चुनिंदा संस्थानों और बड़े शहरों तक सीमित माना जाता था। सरकार द्वारा अब परिषदीय और केजीबीवी विद्यालयों में संगोष्ठी, टेक्नोलॉजी आधारित विशेष कक्षाएं, नवाचार क्विज और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक सोच और इनोवेशन कल्चर विकसित करने की तैयारी की जा रही है।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रदेश के सभी परिषदीय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 'भारत इनोवेट्स 2026' कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत मई 2026 के दौरान विद्यालयों में शिक्षकों और छात्र-छात्राओं की सहभागिता से विभिन्न नवाचार आधारित गतिविधियां कराई जाएंगी। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों में विकसित भारत के नवाचार परिदृश्य विषय पर संगोष्ठी, डीप टेक्नोलॉजी विषय पर विशेष कक्षाएं, भारत क्विज- भारत के नवाचार को कौन जानता है? प्रतियोगिता तथा निबंध लेखन जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इन गतिविधियों का उद्देश्य बच्चों को केवल सैद्धांतिक जानकारी देना ही नहीं, बल्कि उनमें जिज्ञासा, रचनात्मक सोच और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना है। योगी सरकार की रणनीति है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी देश और दुनिया में हो रहे तकनीकी बदलावों और नवाचारों से परिचित हों। यही कारण है कि अब परिषदीय विद्यालयों में भी इनोवेशन और रिसर्च आधारित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जब बच्चों को शुरूआती स्तर पर वैज्ञानिक सोच, तकनीक और नवाचार से जोड़ा जाएगा तो वे भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे। विद्यालयों में कार्यक्रमों के आयोजन के लिए स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं और विशेषज्ञों का सहयोग भी लिया जाएगा। शासन ने निर्देश दिए हैं कि गतिविधियों को अधिक प्रभावी और सहभागितापूर्ण बनाया जाए, ताकि अधिक से अधिक छात्र-छात्राएं इसमें शामिल हो सकें। इसके साथ ही विद्यालयों में आयोजित गतिविधियों की फोटो, वीडियो और नवाचार से जुड़ी जानकारियों का दस्तावेजीकरण भी किया जाएगा। योगी सरकार पहले ही निपुण भारत मिशन, स्मार्ट क्लास, डिजिटल मॉनिटरिंग और स्कूल कायाकल्प जैसे अभियानों के जरिए शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने पर काम कर रही है। अब भारत इनोवेट्स 2026 अभियान को उसी व्यापक विजन का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी भविष्य की तकनीक और नवाचार संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

भाजपा द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला प्रशिक्षण महाअभियान की तैयारियों को लेकर की गई बैठक

प्रशिक्षण महाअभियान 23 एवं 24 मई को अग्रसेन भवन में होगा

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। भाजपा नोएडा महानगर द्वारा 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला प्रशिक्षण महाअभियान' की तैयारियों को लेकर एक बैठक जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष महेश चौहान के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में अभियान की रूपरेखा, व्यवस्थाओं एवं कार्यकताओं की जिम्मेदारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष महेश चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला प्रशिक्षण महाअभियान' का आयोजन नोएडा महानगर में 23 एवं 24 मई को अग्रसेन भवन में किया जाएगा। इस प्रशिक्षण अभियान के माध्यम से भाजपा कार्यकताओं को संगठन की रीति-नीति, विचारधारा एवं कार्यपद्धति से परिचित कराया जाएगा। साथ ही जनसंघ से लेकर भाजपा के वर्तमान विस्तार, संगठनात्मक मजबूती, सोशल मीडिया एवं आईटी के सकारात्मक एवं प्रभावी प्रयोग की बारीकियों पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष महेश चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा के संकल्प के साथ कार्य करने वाला एक वैचारिक संगठन है। प्रशिक्षण अभियान कार्यकताओं को संगठन की विचारधारा से और अधिक मजबूती से जोड़ने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया एवं आईटी का सकारात्मक उपयोग संगठन की ताकत को और अधिक बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रत्येक कार्यकर्ता को पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित एवं जागरूक होना आवश्यक है। बैठक में प्रमुख रूप से चंदगीराम यादव, अमित त्यागी, ओमवीर अवाना, करतार सिंह चौहान, मनीष शर्मा, युद्धवीर चौहान, महेश अवाना, उमेश त्यागी, डिंपल आनंद, विनोद शर्मा, प्रज्ञा पाठक, अर्पित गोयल, राजकुमार झा, पुष्पा रावत, मीनाक्षी चौहान, रामकिशन यादव, शशिधर उपाध्याय, नीरज चौधरी, प्रदीप चौहान, दीनबंधु कुशवाहा, मुक्तानंद शर्मा, पप्पू प्रधान, इंद्राज खटाना, मोनिका श्रीवास्तव, सुनीता शर्मा, ज्योति सक्सेना, मधु चौधरी, चरणसिंह प्रधान, विष्णु शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

वेदपुरा गांव में युवक की गोली मारकर हत्या

ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट के वेदपुरा गांव में बुधवार रात करीब 10 बजे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना गांव के बाहर की है। युवक की पहचान वेदपुरा निवासी दीपक नागर (28) के रूप में हुई है। वारदात के वक्त दीपक दिल्ली के गाजीपुर स्थित कंपनी जा रहा था। ग्रामिणों के मुताबिक बाइक सवार हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि हमलावरों ने दीपक को 5 से 6 गोलियां मारी हैं। वारदात की खबर मिलते ही देर रात तक अस्पताल में ग्रामीणों की भीड़ जमा रही। इकोटेक-3 कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही हैं।

समाज को बांटने वाले बयान राष्ट्रहित के लिए घातक: ओमवीर आर्य

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

ग्रेटर नोएडा। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता ऐडवोकेट ओमवीर आर्य ने बताया कि वर्तमान समय में देश सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में सार्वजनिक जीवन से जुड़े नेताओं और जिम्मेदार व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शब्दों का चयन अत्यंत सावधानी और जिम्मेदारी के साथ करें। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा दिए गए कुछ बयानों ने विभिन्न समाजों में असंतोष और नाराजगी पैदा कर दी है। ब्राह्मण समाज पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी हो या गुर्जर, जाट और अहीर समाज को लेकर दिए गए कथन, ऐसे शब्द किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक समाज में स्वीकार्य नहीं माने जा सकते। किसी भी समाज की महिलाओं की गरिमा पर प्रश्न उठाना न केवल अनुचित है बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के मूल मूल्यों के भी विपरीत है। भारत की परंपरा सदैव 'नारी सम्मान' और 'सामाजिक सौहार्द' की रही है। यहां हर समाज ने राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजकुमार भाटी को किसने ये अधिकार दे दिया कि वह गुर्जर और जाट समाज की स्त्री जाती का अपमान करे, वह अपना ज्ञान अपने पास रखे। एक बुजुर्ग सामाजिक कार्यकर्ता कुवंरपाल भाटी ने चर्चा के दौरान बताया कि जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक साथ हुआ करते थे, तब विधानसभा में ब्रह्मदत्त विधायक जैसे वरिष्ठ ब्राह्मण नेता ने अंग्रेजी शासनकाल से चली आ रही उन धारणाओं को हटाने के लिए आवाज उठाई थी, जिनमें गुर्जर समाज को अपराध से जोड़कर देखा जाता था। ब्रह्मदत्त बाद में केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे और उन्होंने सामाजिक सम्मान तथा समानता के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। सामाजिक लोगों का कहना है कि इतिहास और धार्मिक प्रसंगों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। महाभारत और द्रोपदी जैसे उदाहरणों को संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत करना भारतीय संस्कृति की गरिमा के विपरीत माना जा रहा है। भारतीय परंपरा में कुंती माता, गांधारी माता तथा अन्य पतिव्रता नारियों के आदर्शों को सदैव सम्मान दिया गया है। इसलिए किसी भी समाज की महिलाओं के बारे में असम्मानजनक टिप्पणी करना पूरे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है। लोगों ने कहा कि ब्राह्मण, गुर्जर, जाट, अहीर, राजपूत, वैश्य, दलित और अन्य सभी समाजों ने देश की स्वतंत्रता, संस्कृति और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसी एक समाज को नीचा दिखाकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास अंततः सामाजिक विभाजन को जन्म देता है।